an>

Title: Discussion on the motion to consider Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we are taking up item no. 14 in the List of Business namely, the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move*:

> "That the Bill to declare certain Indian Institutes of Information Technology established under public-private partnership as institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto, be taken into consideration."

महोदय, प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में ट्रिपल आई. टी. के 20 संस्थान तैयार करने का निर्णय हुआ, क्योंकि आज भारत आई. टी. का एक सॉफ्ट पॉवर दुनिया में माना जाता है। दुनिया में आई. टी. के क्षेत्र में काम करने वाली एक भी कंपनी ऐसी नहीं है, जहां भारत की बुद्धि काम में न हो और भारत के नौजवान वहां अपने बहुत परिश्रम से नये-नये मुकाम हासिल कर रहे हैं।

Sir, I was Chairman of the Information Technology Task Force in 1995 in my State of Maharashtra. But since then I have seen the progress made in the Information Technology sector. When Atal Bihari Vajpayeeji was the Prime Minister and you were also a Minister, at that time we were dreaming of having 50 billion dollars of export through IT industry. But today it is much more than that. We have achieved a lot and our IT experts are going all over the world. We have been recognized world over as the IT soft power. To promote this IT industry, we provided IIITs in Government sector. Then, as many industries were also coming up to help this sector, it was felt that there should be public-private partnership and 20 such IIITs with public-private partnership were mooted in 2010. Now, nearly 15 IIITs are already operational in the country. This year, they will be graduating for the first time and the IIIT Bill provides for granting degrees to their students. But IIIT public-private partnership mode is a different mode because there are different stakeholders. In IIITs, it is only the Central Government but in IIITPPP, it is the Central Government, the State Government and the private sector. So, instead of amending the law because it would have been a very complex exercise, हम इस बिल को इसलिए लाए हैं कि इसे पास करने में सभी की सहमति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, इसमें जो अच्छे सुझाव आएंगे उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जो छात्र इस साल पास होंगे उनको डिग्री देने का पॉवर उस संस्थाओं को नहीं है वह इससे मिलेगी, इस बिल का मूल परपस यही है। इस बिल पर जो चर्चा होगी इससे आईआईआईटी के कारोबार में भी सुधार होगा और आईटी के बारे में जो सुझाव आएंगे, उस पर सरकार विचार करेगी, यह बिल चर्चा के लिए प्रस्तुत है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to declare certain Indian Institutes of Information Technology established under public-private partnership as institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, यह महत्वपूर्ण बिल है, एक जरूरी बिल है। जैसा बताया गया कि ट्रिपल आईआईटी के माध्यम से डिग्री भी दी जाएगी, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा सरकार इस बिल के माध्यम से दिला रही है। इस बात का हम स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर इस बिल में अच्छे प्रस्ताव हैं, उन पर हम पूरी तरह से सहमति व्यक्त करेंगे, कुछ अपना सुझाव भी देंगे, मगर उससे पहले, मैं एक राजनीतिक बात कहना चाहूंगा, मंत्री जी ने जब इस बिल को रखा तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया कि उन्होंने आईटी सेक्टर को इतना आगे बढ़ाया।

आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद किया, नःसंदेह सभी ने अपना योगदान दिया था। इस सेक्टर को राजनीतिक दÂिष्ट से न देखा जाए, अगर हम इतिहास में जाएंगे, मैं ट्रिपल आईआईटी का इतिहास भी बताऊंगा। ट्रिपल आईटी की पहली टास्क फोर्स भारत सरकार के स्तर पर बनी, वह वर्ष 1992 में बनी, उस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी, डॉ. पी.जी. रेड्डी जी ने इसका नेतृत्व किया, वर्ष 1995 में प्रस्ताव रखा और पहला ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर वर्ष 1997 में स्थापित किया गया। वर्ष 2002 में उसका नाम बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर दिया गया, मगर उसकी स्थापना वर्ष 1997 में हो चुकी थी। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है।

हालांकि मौजूदा सरकार ने राजीव आवास योजना का नाम भी बदल दिया, राजीव जी ने भी देश के लिए शहादत दी थी, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री जी के नाम पर कर दिया गया, उन्होंने भी देश के लिए शहादत दी। ...(व्यवधान) लेकिन हमने नाम नहीं बदला, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही उसे रहने दिया। हम ट्रिपल आईटी के इतिहास में दोबारा जाएं तो वर्ष 2010 में कैबिनेट ने ...(व्यवधान) आज 20 संस्थानों को नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा देने की बात हो रही है, कैबिनेट ने वर्ष 2010 में प्रस्ताव पारित किया था कि 128 करोड़ रुपये की लागत से संस्था की स्थापना की जानी थी, उस भावना को आगे बढ़ाया। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस का सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था, जब आईआईटी और एम्स की स्थापना की गई थी। खड़गपुर के चिलजी में जो डिटेंशन सेंटर था भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सांसद इस चीज को मजाक में ले रहे हैं। आप 70 साल के इतिहास को बदल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कैलिफोर्निया में जाकर सिलीकॉन वैली में सुंदर पिचाई की प्रशंसा करते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर से निकल कर गए हैं जिसकी स्थापना की गई थी। आपने उसी को आगे बढ़ाया है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, हम मिल कर देश को आगे लेकर जा सकते हैं। आपने जो योगदान दिया आपकी सरकारों के योगदान को हम कम आकलन नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करना उस सरकार के पुरूषार्थ से धोखा करना होगा।

मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, आपने कहा कि वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि यह 50 बिलियन तक पहुंचे, हमें खुशी है कि आईटी सेक्टर आज 50 बिलियन नहीं बल्कि 155 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। आईटी इनेबल सर्विसेज हमारी जनसंख्या के एक प्रतिशत को रोजगार देने का काम करता है। दुनिया में 56 प्रतिशत मार्केट शेयर हिन्दुस्तान के आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज सेक्टर का है। इसके साथ ही यह भी बताना चाहिए कि इसकी शुरूआत कैसे हुई, इसका दीप कहां प्रज्जवलित हुआ, वर्ष 1984 में जब राजीव गांधी जी के समय में कम्प्यूटर पॉलिसी आई, वर्ष 1985 में भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई और वर्ष 1986 में भारत सरकार की साफ्टवेयर पॉलिसी बनी। तब यह सैक्टर दुनिया में हिन्दुस्तान में सुपर शक्ति के रूप में आया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज इस बिल पर बोल रहा हूं। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की थी। मैंने इनफोसिस में बंगलौर, पुणे और अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर

के रूप में काम किया। यह बात सही है कि मेरे बाप-दादा ने खेती की है, मेरी रुचि भी बचपन से खेती की तरफ रही थी, लेकिन प्रोफेशनल शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के माध्यम से की। आप यह बिल लेकर आए हैं, उस लिहाज से आईआईआईटी की स्थापना बहुत जरूरी थी। हमें इस बात की खुशी है कि जावड़ेकर जी इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी गहरी समझ है, मैं जानता हूं। मैंने जब इंजीनियरिंग की, उसके बाद टैक्सटाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इनफोसिस में पहुंचा, वहां छः महीने ट्रेनिंग नए सिरे से कराई गई। उनका खुद का इंस्टीट्यूट था, जहां नए सिरे से ट्रेनिंग कराते थे। मैसूर में ट्रेनिंग कराई गई थी। आईआईआईटी की पार्टनरशिप कंपनियों और कॉरपोरेशन के साथ है, मैं समझता हूं कि यह बिल इस दिशा में आईटी स्किल को आगे ले जाने का काम करेगा।

महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसे राजनीतिक दृÂिष्टकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। Some things are apolitical and this is the beauty of India. What we can achieve together, certain things should be seen from that perspective. I want to ask the HRD Minister regarding two IIIT projects. 20 प्रोजेक्ट की स्थापना की जानी थी, इसमें से दो प्रोजेक्ट आईआईआईटी अमेठी और सोनीपत थे। सोनीपत मेरे संसदीय क्षेत्र में है। क्या कारण है कि आईआईआईटी अमेठी को बंद कर दिया गया और इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया, जो छात्र पढ़ रहे थे, उनको भी अमेठी से इलाहाबाद भेजा गया। आईआईआईटी सोनीपत मेरे संसदीय क्षेत्र में है। 2013 में पल्लम राजू जी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने फाउंडेशन रखी थी, इस पर कार्य शुरु हो गया था। जैसे ही सरकार बदली, इसका कार्य रुक गया। अभी हाल ही में खबर आ रही है कि इसकी जगह चयनित की जानी है जबकि इसका कार्य शुरु हो गया था। मैं दो लोकसभा क्षेत्रों की बात कह रहा हूं जहां विपक्ष के सांसद हैं। आपको तो बढ़कर काम करना चाहिए, हम सब मिलकर देश को आगे ले जाने का काम करेंगे।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी आईआईआईटी अमेठी और सोनीपत के बारे में जानकारी दें क्योंकि जब बाकी आईआईआईटी में काम हो रहा है तो ये दो आईआईआईटी में किन कारणों से काम नहीं हो पाया है, कैम्पस स्थापित नहीं हो पाए?

महोदय, जहां तक आईटी सैक्टर की बात है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रतिशत देश में नौजवानों को रोजगार देने का काम आईटी सैक्टर करता है। पिछले कुछ दिनों में इस सैक्टर पर रोजगार देने की कैपिसिटी पर बादल मंडरा रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं, एक कारण आर्थिक मंदी है। जिस तरह से पिछले एक-दो साल से आर्थिक मंदी हुई है, डिमांड कम हुई है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण कारण है दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट पालिसी आईटी सैक्टर में बहुत वृद्धि हुई है। दो देशों में हमारी बड़ी मार्किट हैं। जब से अमेरिका में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, इसमें एक नीति लाई गई है - Buy American' and 'Hire American' rule. हायर अमेरिकन्स रूल पालिसी में एच-1बी वीज़ा है। मुझे याद है जब मैं बंगलौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पहली बार अमेरिका गया था, एच-1बी वीज़ा पर गया था। मेरे जैसे बहुत लोग गए थे। सुंदर पिचाई जी की बात हुई है। आज अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिलिकन वैली की बहुत प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज वहां पर डामिनेट हमारे देश के मूल निवासी करते हैं। एच-1बी पालिसी में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम इतनी सख्ती बरती है, कैसे, उन्होंने दो-तीन चीजें की हैं, एक फास्ट ट्रैकिंग सस्पेंड कर दी, दूसरी बात 60,000 डॉलर इनकम जिस इनकम पर हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, उसकी लिमिट बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार डॉलर कर दी। मैं समझता हूं कि हमारे देश के इंजीनियर्स को एक्सलूड करने की तरफ अमेरिका की एच-1बी पालिसी बनी है। अमेरिका 70 प्रतिशत एच 1 बी वीजा हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इश्यू करता है। इस वजह से एकदम कटौती आयी है।

मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मकेनसियन कम्पनी की रिपोर्ट आयी कि अगले तीन वर्षों में आईटी सैक्टर में कटौती होगी। यह आपके लिए बड़े सोचने का विषय है, क्योंकि आपका वायदा था कि दो करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन आपका लेबर ब्यूरो रहा है कि पिछले साल केवल दो लाख नौकरियां दी गयीं। यह आप लोगों के लिए सोचने का विÂषय है कि हिन्दुस्तान सुपर शक्ति के रूप में बहुत तेजी से आईटी सैक्टर में आगे बढ़ रहा था, अब मकेनसियन कम्पनी ने एक प्रिडक्शन की है कि अगले तीन वर्षों में हर साल आईटी सैक्टर में दो लाख नौकरियों की कटौती होगी। जो ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट्स से ग्रेजुएट्स निकलेंगे, उनके भविष्य के बारे में हमें चिंता करनी है।

पिछले वर्ष लार्सन एंड टूब्रो में 14 हजार साफ्टवेयर इंजीनियर्स की छंटनी की गयी। इनफोसिस में 9 हजार साफ्टवेयर इंजीनियर्स की छंटनी की गयी। नौकिया में 6600 साफ्टवेयर इंजीनियर्स, कॉग्निजेंट में 6 हजार, एचडीएफसीबैंक में 4500 और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसंज में 3 हजार इंजीनियर्स की छंटनी की गयी। मैं टीसीएस के बारे मे कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी जीत हुई है। आपकी जीत के बाद अखबार में कॉरपोरेट सैक्टर से जुड़ी हुई न्यूज आयी कि टीसीएस, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों से लखनऊ में था, उन्होंने लखनऊ में अपना दफ्तर बंद कर दिया। वहां जितने भी इंजीनियर्स थे, उन सबकी नौकरी चली गयी। मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

जैसे मैंने कहा कि ये जो कटौतियां हो रही हैं, उसके दो मूल कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे देश में आर्थिक मंदी हुई और दूसरा दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट पालिसी, जिसमें एच 1 बी वीजा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार और प्रधान मंत्री जी को स्वयं जवाब देना चाहिए, क्योंकि वे अभी अमेरिका गये थे। अमेरिका में आपस में बहुत से ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई और सहयोग की बातें आगे बढ़ी। इसमें एच 1 वीजा की भी बात है। अमेरिका ने हमसे अपनी एक्सपोर्ट पालिसी को लेकर हिन्दुस्तान की मार्केट खुलवाने के लिए बात की, लेकिन एच 1 बी पालिसी में जो रिस्ट्रक्शन्स अमेरिका लेकर आया है जिसकी वजह से हमारे देश के आईटी सैक्टर में इतना ले ऑफ हो रहा है, उसे खुलवाने के लिए क्या बात की, यह प्रधान मंत्री जी बतायें।

दूसरा देश आस्ट्रेलिया है, चूंकि जूली बिशप आयी हुई हैं, जो आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री हैं। आज हमने सुषमा स्वराज जी के साथ उनकी तस्वीर देखी है। यह देखकर हमें खुशी हुई, क्योंकि आस्ट्रेलिया हमारा एक मित्र देश है। आस्ट्रेलिया का एक 447 वीजा प्रोग्राम है, जिसे उसने बंद कर दिया है। इससे हिन्दुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को भी अमेरिका में काम करने में बहुत परेशानी आयेगी। मैं समझता हूं कि ट्रिपल आईटी से ग्रेजुएट आ रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दस वर्षों से काउंसिल ऑफ आईआईटीज में एज ए मैम्बर रहा हूं, क्योंकि काउंसिल ऑफ आईआईटीज में एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल आईटीज में भी काउंसिल ऑफ ट्रिपल आईटीज की स्थापना की गयी है। आप वहां पर चेयरमैन हैं और उसमें दो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि काउंसिल ऑफ आईटीज में मेरा काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। अब कुछ आईआईटीज ब्रांड बन चुके थे, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पवई, आईआईटी खड़गपुर। उनके एक्सटैंशन सैंटर की स्थापना करने की बात काउंसिल ऑफ आईआईटीज ने एडॉप्ट की, जो मेरा ही प्रस्ताव था। आज आईआईटी दिल्ली के दो एक्सटैंशन सैंटर हरियाणा में ही खुल रहे हैं। दूसरी जगह पर भी एक्सटैंशन सैंटर खुल रहे हैं। ट्रिपल आईटीज का भी यह बहुत बड़ा स्कोप है। इस बिल में उसका प्रावधान नहीं है। जो 20 ट्रिपल आईआईटीज हैं, इनमें जो आपके फ्लैगशिप ट्रिपल आईटीज हैं, जो ब्रांड ट्रिपल आईटी बेंगलुरू, ट्रिपल आईटी हैदराबाद आदि के एक्सटैंशन सैंटर छोटे शहरों में खुल पायेंगे तो वहां के छात्र भी इसमें इन्वाल्व हो सकेंगे, क्योंकि आईटी सैक्टर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके खुलने के लिए बहुत बड़ा इफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजायी है, इसलिए मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि यह सैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश के लिए एक मूल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 21वीं सदी में सुपरशक्ति बनना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो उसमें यह सैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जब सिलीकेन वैली गये, तो उन्होंने वहां की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि --

California is one of the last places in the world to see the sun set. But, it is here that new ideas see the first light of the day. आज सिलिकॉन वैली, अमेरिका के मुकाबले में दुनिया के आईटी ट्रेड के 56 प्रतिशत को हिन्दुस्तान डॉमिनेट करता है। हमारा बैंगलोर का आईटी सेक्टर वहां की सिलिकॉन वैली के मुकाबले में खड़ा है। प्रधानमंत्री जी बैंगलोर की भी तारीफ करें। प्रधानमंत्री जी कहें कि अगर कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली दुनिया को रास्ता दिखा रही है तो बैंगलोर की सिलिकॉन वैली आज उससे भी आगे बढ़ चुकी है। इसमें सभी का पुरुÂ ार्थ है, अगर पिछले 70 वÂर्षों की बात करें तो आप लोगों का भी पुरुÂार्थ है कि बैंगलोर आज दुनिया को डॉमिनेट कर रहा है। हम उसकी कल्पना करें और इस सेक्टर को किस तरीके से मजबूत किया जाए। एक मर्फीज लॉ है -

"Things left on their own, things tend to get from bad to worse."

अभी आईटी सेक्टर में ऐसा ही लग रहा है। आपने आईआईआईटीज के लिए अच्छी पहल की है, लेकिन आईटी सेक्टर में लग रहा है कि things have been left on their own. That is why, things are going from bad to worse. इस चीज को कैसे बदलें?

आखिर में, मैं उस इंजीनियर की व्यथा बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसके पास रात को 12 बजे फोन आया कि कल सुबह दस बजे से आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। वह ऑडियो बहुत वायरल हुआ। यह जो अनसर्टेनिटी आई है, हम अपने समय में बहुत गर्व से कहते थे कि हमारी नौकरी इनफोसिस में लग गयी है। जब हम अपना घर छोड़कर बैंगलोर गए थे, हम बहुत गर्व से कहते थे कि इनफोसिस में हमारी नौकरी लग गयी है और हम देश के निर्माण में, देश को आगे लेकर जाने में अपना योगदान करेंगे। वही दिन दोबारा वापस आएं, आईटी सेक्टर देश में और दुनिया

का नेतृत्व करने में अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष जी, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और ऐतिहासिक विधेयक को लाने के लिए अपने विजनरी और दूरदÂ ष्टा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रशंसा करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। यह बिल निश्चित रूप से इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में शिक्षा, शोध, प्रचार और प्रसार में नए युग का सूत्रपात करेगा। यह बिल हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से देश में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा का एक ऐसा दूरगामी, प्रभावी और सक्षम तंत्र खड़ा होगा, जो न केवल हमारी घरेलू विदेशी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सामरिक श्रेष्ठता को पूरी दुनिया में सर्वश्रेÂष्ठ रूप में परिवर्तित भी करेगा। आज विश्व का परिवेश जिस तेजी से बदलता जा रहा है, उस प्रतिस्पर्धा में हम पीछे न छूट जाएं और विश्व के स्तर पर हम केवल उनके साथ कदमताल न करें, बल्कि सारे विश्व का हम नेतृत्व कर सकें, इस दिशा में यह बिल निश्चित रूप में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे भी शिक्षा का सर्वांगीण विकास, मानव संसाधनों के विकास एवं समाज के विकास में उसके योगदान का जो महत्वपूर्ण अंग एवं भूमिका है, उसी से यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरकर आया है। निश्चित रूप में ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो जनशक्ति का विकास करेगा और न केवल देश में, बल्कि हमें पूरे विश्व में शिखर पर लेकर जाएगा। ऐसा यह महत्वपूर्ण बिल आज आया है, मैं इसके लिए मंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, कुल मिलाकर तीन अध्यायों एवं 48 खण्डों में विभिन्न चीजों को जोड़ा गया है। सार्वजनिक सहभागिता की परिभाÂषा क्या होगी, किस तरीके से इसकी स्थापना होगी, किस तरीके से केन्द्र, राज्य और इंडस्ट्रीज के मध्य किस तरीके का समन्वय होगा, केन्द्र सरकार इसका प्रस्ताव किस तरीके से करेगी, कैसे एमओयू इसके लिए तैयार होगा और इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका क्या होगी, इस बिल के कई खण्डों में बहुत स्पष्ट तरीके से व्याख्या की गयी है। गवर्निंग बोर्ड का संयोजन कैसा होगा, कितने सदस्य होंगे, जो 15 सदस्य होंगे, उनके क्या-क्या अधिकार होंगे, किस रूप से यह आगे चलेगा, सीनेट की शक्तियां एवं कार्य क्या होंगे आदि चीजों को इसके तमाम खण्डों में बहुत स्पष्ट तरीके से विभाजित किया गया है। समन्वय कैसे होगा, इसके लिए भी प्रावधान है। इस संस्थान की फंड्स की दिशा क्या होगी, उस दिशा में भी काम किया गया है। यह संस्थान स्थिर हो सके, 15 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना कर, उनको डिग्री देना, विश्व स्तर पर उनकी सामरिकता और उनके महत्व को बढ़ाने का जो अभियान इस बिल के माध्यम से किया गया है, इसमें किस तरह से स्थिर तरीके से आगे बढ़ सकता है और यदि कभी विवाद होता है तो विवादों को किस तरीके से हल किया जा सकता है, यह भी इस बिल में है। इस बिल में एक-एक बिन्दु 48 खंडों के अंतर्गत समाहित हैं।

उपाध्यक्ष जी, हम विश्व की वित्तीय अनिश्चितता के बीच पूरी दुनिया का आशा का केन्द्र बन कर उभरे हैं। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व हम विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में आकर खड़े हैं। हमारी अद्वितीय आर्थिक प्रगति के पीछे निश्चित रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है, हमारी जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी से आता है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता का यह प्रमाण है। वर्ष 2016-17 में हमारा सॉफ्टवेयर निर्यात 116 बिलियन डॉलर का था और आज 40 लाख से भी अधिक प्रत्यक्ष रोजगार हो रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों-करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है।

उपाध्यक्ष जी, नासकॉम के अनुसार वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र में 30 लाख नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह विश्व के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, एक नये युग का सूत्रपात होगा।

जैसा कि हमारे मित्र ने कहा है कि आज हिन्दुस्तान में जो बाहर से विदेशी मुद्रा आती है, उसमें चीन भी पीछे छूटा है, इस समय हिन्दुस्तान नम्बर एक पर है। आईटी के क्षेत्र से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। इसका मतलब है कि हम हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर आगे जाने की स्थिति में हैं। यह एक संयोग है कि हमारे भारतवासी या भारत मूल के लोग विश्व के आईटी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो शीÂान कंपनियां हैं - यदि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को देखें तो वह सत्या नडेला हैं, गुगल के सीईओ को देखें तो वह सुंदर पिचाई हैं, आडोबे के सीईओ को देखें तो वह सान्तनु नारायण हैं, कॉग्निजैंट के सीईओ को देखें तो वह फ्रांसिस्को डिसूजा हैं, नेट एप के सीईओ को देखें तो वह जॉर्ज कुरियन हैं, नोकिया के सीईओ को देखें तो वह राजीव सूरी हैं और ग्लोबल फाउंड्री के सीईओ को देखें तो वह संजय झा हैं और जेरॉक्स कंपनी के सीईओ को देखें तो वह अशोक भामरी हैं, दुनिया के शीर्ष स्थानों पर रहने वाली कंपनियों में भारत का अधिपत्य है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि इस देश में विश्व के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया जाये, ऐसे मानव संसाधन को तैयार किया जाये जो और ऊंचाइयों पर पहुंचे और भारत को सारे विश्व में नेतृत्व प्रदान करें, आज भी विश्व का नेतृत्व भारत के ही लोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सिलकॉन वैली की चर्चा की गयी है। जापान, सिंगापुर, हॉलैंड, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका हो या केन्या हो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल, इन सभी स्थानों पर तीस प्रतिशत से भी अधिक हिन्दुस्तानी हैं। नासा में दस में से चार लोग हिन्दुस्तान से हैं। नासा, जो विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, उसमें दस में से चार हिन्दुस्तानी हैं, हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। इसलिए यह आईआईआईटी का जो एक्ट आया है, उसके लिए मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पहले भी एक्ट था, लेकिन वह निजी सहभागिता के आधार पर नहीं था, उसमें संशोधन करके जिस तरीके से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का इसमें आना जरूरी था, क्योंकि इंडस्ट्रीज में किस तरीके के लोगों की जरूरतें हैं, उनको तैयार किया जाये, यह बहुत जरूरी है। इसलिए यह जो बिल आया है, यह न केवल विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करेगा बल्कि 15 पीपीपी मोड के संस्थानों को वैधानिकता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित होने के पश्चात इसमें स्वायत्तता स्वतः हासिल हो रही है। यह गवर्निंग बॉडी का संयोजन सुनिश्चित कर शिक्षा के लिए शोध का उचित वातावरण इस देश के अंदर खड़ा होगा, वह निश्चित रूप से सारे विश्व को लीड करेगा, नेतृत्व देगा।

महोदय, इस बिल का उद्देश्य संस्थानों में स्वायत्तता, जवाबदेही के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेÂष्ठ शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना है। हमारे छात्रों को, हमारे संकाय को, हमारे वैज्ञानिकों को विश्व के मानदंड पर कैसे स्थापित कर सकें, यह इस बिल का मूल उद्देश्य है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि भारत विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र बने, यह बिल इसमें सहयोगी होगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप स्टैंड-अप जैसे क्रांतिकारी, युगांतरकारी अभिनव मिशन को पूरा करने के लिए यह बिल नींव का पत्थर निश्चित रूप से साबित होगा। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, आज ढाई लाख गांवों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का अभियान है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बिल से अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इस बिल में औद्योगिक साझीदारी से उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार जो पाठ्यक्रम बनेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है और संस्थानों की गवर्निंग में यह बिल सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगा। संस्थानों में स्टार्ट-अप और फंडिंग की क्या व्यवस्था होगी, उसकी भी पूर्ति करेगा। इसके लिए हर विÂाय को माननीय मंत्री जी ने इस बिल में स्पÂष्ट किया है और शिक्षा तथा शोध के उच्चतम मानदंड स्थापित करने की मंशा से गवर्निंग बोर्ड की नीति बनाने के लिए सुनिश्चित किया गया है, उसमें बोर्ड को डिग्री, डिप्लोमा, छात्रवृत्ति देने की स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है। संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता संकाय तय करेगा, इसलिए उस पर भी नियंत्रण करने का इस बिल में प्रावधान किया गया है। उच्च स्तरीय फैकल्टी के सदस्यों के चयन हेतु बोर्ड रणनीति बनाएगा, बोर्ड संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेगा, राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रतिÂिष्ठत शिक्षाविद, उद्योगपति चयन समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे। सभी प्रकार के लोगों को इस बिल में समाहित किया गया है और निश्चित रूप में यह सुनिश्चित किया गया है कि चयन प्रक्रिया की उत्कृष्टता हमेशा-हमेशा बरकरार रहे। किसी भी संकाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने संसाधनों को समयबद्ध तरीके से विकसित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और इस बिल में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये जो पन्द्रह संस्थान हैं, वे अपने आर्थिक संसाधन जुटाने की रणनीति का सृजन करें और उसका क्रियान्वयन करके पांच वर्ष के अंदर अपने आप में स्वायत्त बन सकें। पांच साल में वे अपने लिए आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रख सकें, यह भी इसमें सुनिश्चित किया गया है।

महोदय, जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में हम जिसको लीड कर रहे हैं, उस क्षेत्र में यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूँ। हिमालय का जो क्षेत्र है, उसकी जो मानव-सम्पदा है, वह पूरे विश्व के लिए अनोखी है। उसमें प्रखरता है, शालीनता है, उसमें मेहनत करने का ज़ज्बा है। हिमालय के क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से, जहाँ पूरी दुनिया को पर्यावरण की पहली पाठशाला होने का लाभ देता है, जहाँ वह ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, वह एशिया का वाटर टावर है। यह लोगों को जल भी देता है, जीवन भी देता है, ऐसे हिमालय के परिदृश्य को बचाये रखने के लिए इससे बड़ा उद्योग कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड की धरती पर एक दीपत आईटी की स्थापना की जाए। जब मैं उत्तराखण्ड का मुख्यमंत्री था, तब श्रीनगर में एक एन.आई.टी. सेन्टर लेकर गये थे। उत्तराखण्ड में इसकी स्थापना से वहाँ की शांत, सुन्दर, सुरम्य अध्ययन के अनुकूल वातावरण होगा। हमारे पास बहुत ही प्रखर, समर्पित और मेहनती युवा हैं। वे जहाँ सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर कुर्बानी देते हैं, राष्ट्र के विकास में धुरी बनकर वे आगे बढ़ते हैं, वहाँ इस क्षेत्र में भी वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ प्रदूषण रहित सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग होगा। इससे अच्छा वातावरण और कहीं नहीं मिल सकता है।

इसलिए मंत्री जी आज जो यह बिल लाये हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और इसी अनुरोध के साथ कि वे हिमालय और उत्तराखण्ड पर भी दृष्टि डालेंगे, यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the Indian Institutes of Information Technology (PPP) Bill, 2017 which was introduced by the hon. Minister of HRD on 10th April of 2017. This is really a good moment and good starting. When we are in a pathetic situation, our technical education is also in a pathetic and panic situation.

This Bill provides for establishment of institutes through collaboration among the Centre, the State Government and the industry partners, which is most important. The capital investment for such a venture would be borne in the ratio of 50:35:15 among the Centre, the State Government and the industry partner.

Here, I would like to say that with the advent of GST, all the resources of the States are taken over by the Centre and the States have very little means. So, in the collaborative partnership among the three, the State Government will also be giving land measuring between 50 acres and 100 acres free of cost. That being so, the expected capital investment for States may be reduced to 20 per cent and the Centre may increase its own share to 65 per cent, keeping the share of the industry unchanged.

Sir, we welcome the initiative of the Government of opting for the PPP mode for developing such institutions. This will go a long way, in the long run, in understanding the needs of the industry while the students study at the colleges. This is the most important thing. This will help bring in necessary modifications – it is mandatory now-a-days - in the curriculum itself so that the students are equipped to face the challenges of the outside world when they go out of the colleges. This is a good initiative. They will become intellectuals.

Here, my small suggestion is that this mode of PPP should be extended to the self-financed institutions in engineering and medical fields also. I think, this is the time to go for it. Presently, the self-financed engineering colleges are in doldrums and if they were to be brought out of the woods, then the PPP mode is the only solution. This PPP mode really is a revolution. The Government may think over it and bring in a comprehensive Bill for this purpose in future.

Sir, I would like to take this opportunity to point out one or
two issues, through this House, for the consideration and perusal of the hon. Minister of HRD. The first and foremost is the confusion that was created by giving grace marks this year to the 12th class students of CBSE. This had caused considerable delay in publishing the results also. Though everybody agrees – the parents are worried - that there should be normalisation in marks, one similar set procedure is not followed throughout the country. This is my humble suggestion.

Secondly, every Board has different set of procedures for doing this. Unless we have common syllabus and common Board there cannot be clarity on this issue, and there cannot be any equalisation in studies and marks. So, I would urge the Government to firstly ponder over this aspect.

With this observation, I welcome the initiative and congratulate our HRD Minister and this Government and end my speech. Thank you.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017.

The Bill proposes to set-up Indian Institutes of Information Technology in public-private partnership mode. In this model, there will be autonomy in governance that will help in addressing the present challenges faced by the Indian information technology industry in our country. It will help in growth of the domestic information technology market including developing new knowledge areas and creating skilled manpower of global standards.

Presently, our Indian IT sector is going through turbulent times. Most IT companies are witnessing some notable layoffs across the technology sector. With increasing pace of layoffs this year, the number of employees who will lose their jobs are likely to be more compared to last few years.

The Indian startup ecosystem along with big companies has not been able to save itself from various problems like funding and investments. So, it is extremely necessary at this juncture that we create world-class education centers to develop skilled manpower in emerging sectors and address this issue.

As of now, four Indian Institutes of Information Technology have been established at Jabalpur, Kancheepuram, Gwalior and Allahabad, which are public-funded and governed by the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 to provide Under-Graduate as well as Post-Graduate education with specialization in allied areas. The Government proposes to set-up twenty Indian Institutes of Information Technology in public-private partnership mode.

Presently, there are fifteen functional Indian Institutes of Information Technology in public-private partnership mode, which are proposed to be declared as Institutes of national importance. The Indian Institutes of Information Technology set-up in public-private partnership mode is required to be given statutory status that shall enable the Institutes to grant degrees to the students. Every IT Institute shall strive to raise funds for creation of a corpus for self-sufficiency, sustainability and future development of this Institute. The State Government shall identify at least one industry partner, and preferably three industry partners for collaboration and submit a proposal to the Central Government.

The Government hopes that trained personnel from these Institutes shall fulfill the growing demand for skilled, technical manpower in emerging IT sectors and the economy as a whole. The Institutes shall be open to all persons irrespective of gender, caste, creed, disability, domicile and ethnicity -- social or economic background. This is indeed a commendable initiative taken by the Goverment.

Establishing IIITs in Public-Private Partnership and subsequently declaring them as institutes of national importance would help in providing world-class education to students, foster research and development and make the way for India becoming a world-class leader.

These Institutes, when declared as institutes of national importance, is expected to come up as an institution of excellence that would facilitate and promote the competitive advantage of Indian Information Technology products. For competing in the global market, IT Sector requires developing quality products with leading technology and competitive advantage. It would be required to provide the institutes with adequate infrastructure along with their own building.

Many IIITs including Kalyani IIIT, West Bengal do not have their own buildings; they occupy rented premises, resulting in operational problems. Also, parity in fee-structure among the different IIITs would help in promoting standardization and equality. I would request the hon. Minister of Human Resource Development to please note that the Kalyani IIIT, West Bengal has no permanent building.

It is mentioned in the Bill that the investment of capital required for establishing the proposed institute to be borne by the Central Government, the State Government concerned the industry partner in the ratio of 50:35:15 and recurring expenditure during the last five years of operation to be made available by the Central Government. I would like to request the hon. Minister to clarify this point because Government is funding only for five years. After that, what will happen? They will withdraw their funds. Poor students cannot get a chance to join these institutions as these institutions may increase the fees.

We are aware that talented students are leaving the country in search of better options to enhance their academic career. Also people get disenchanted with the low rewards available for their
qualifications and experience, which compels them to migrate to developed countries in search of better options. To attract this talented pool and encourage them to remain in the country, programmes at such Institutions of National Importance should be aimed at providing solutions to current technological challenges in wide domains like Robotics, Artificial intelligence, Cloud Technology, Internet-of-things and Automotive Systems and offer academic and research programmes that integrate engineering design, manufacturing and management with information technology. World class infrastructure along with competent faculty is a must for these Institutes.
Information Technologists' and research graduates from these Institutes can become entrepreneurs and start their own organizations. So I would urge the Government to ensure that the course design, infrastructure and faculty are of world class.

With these few words, I would like to request the hon. Minister to please consider the important points raised by me, on behalf of my Party, while replying to the debate. Thank you, Sir.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017.

I stand to support this bill. Although this bill is about IIITs, it concerns higher education. Therefore, I will briefly speak about related issues too. Everyone demands IITs, IIMs, IIITs and institutes of higher education. But nobody talks about the quality of education. You hear pass-outs from these institutions getting a salary package of up to Rs.40 crore a year, but do you ever hear of the millions of students that pass out and don't get jobs at all? We are all busy demanding buildings, not effective centres of higher learning.

The reality is that we have `entrance' tests, but not `exit' tests. We don't think about where these students go after passing out. Where are they employed? Are they getting jobs or not? We don't ponder over this. According to a 2017 study by an employability assessment company, Aspiring Minds, only 4.77 per cent candidates can write the correct logic for a programme - a minimum requirement for any programming job. This is a deplorable situation. Can we have an official Government survey done about how many people are employable after they pass out from not just IIITs, but also private colleges?

Estimates by NASSCOM in 2012 say that the total figure of training students to make them employable might be as high as two billion annually. This is the amount spent by corporates after the students themselves pay Rs.10 lakh each for getting educated in a private engineering college.

The amount of money being wasted because of inferior teaching and training levels is mind-boggling. Imagine how much money corporations would save if the pass-outs were effective and readily employable. That will definitely benefit the Indian economy immensely.

What is the importance of this Bill? This Bill, therefore, appears to be a step in the right direction. By allowing industry participation in management of IIITs, we will ensure that the right kind of exposure is provided to students before they pass out. The Bill proposes a ratio of 50:35:15 for the Central, State and private investors respectively. The financial burden of the Central Government should be slowly and steadily reduced overtime and handed over to the State and other investors. Decentralised education is the right way to go. Perhaps, it would be better if this set of ratio is not mentioned in the law but issued through regulations after the law is passed. It would be beneficial because then the Government can moderate the share of each parties according to the conditions prevalent in future.

What about the teachers? On March 20, 2017, the HRD Minister admitted in Lok Sabha that teacher recruitment is becoming a serious problem in higher education institutes and that around 205 posts in Central Universities are yet to be filled up, that is, 20 per cent of all posts in national education institutes. Apart from increasing the retirement age of teachers, I would urge upon the Minister to come up with a more permanent solution for the same. Students who pass out are always going after high paying jobs in different companies and they are not encouraged to even think about teaching. It would be a big step to have regular seminars within colleges like IIITs where students are informed regarding opportunities in teaching in different universities. The pay for the teaching jobs might not be as much compared to private jobs with IT companies. So, it needs to be increased and made more and more attractive.I had just said this last year to pay more attention to the 'HR' part of HRD and not just on infrastructure. To construct a building somewhere is easy but creating human resource is a bigger and a more difficult task.

Lastly, I would urge the Government to consider promoting other languages in institutes of higher education, not just Hindi. There is no investment going in to promote regional languages. Do consider this seriously because it would go a long way towards attracting local talent within these numerous IIITs that the Government is setting up. India's strength is in its diversity and language plays a big role.

With these words, I thank the Speaker Madam for giving me the opportunity to speak on this Bill. Thank you.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I thank you very much, Sir. I sincerely, at the first instance, heartily congratulate Shri Prakash Javadekar, the hon. Minister and the Government for introducing such a wonderful Bill -- the Indian Institutes of Information Technology (Public, Private Partnership) Bill -- the Indian Institutes of Information Technology (Public, Private Partnership) Bill -- to the students who are striving hard for the opportunity to get the degrees. I am really proud to say that. Today, I am not going to go to the intricacies of it.

I look at my childhood. It was a transformation in the country going from radio to transistor. It was a wireless technology started first with the transistor. From transistor onwards, the technology within the last ten years as grown up so speedily that, particularly, IT sector has brought a revolution in the world – Google and other people. We are congratulating the people who are working abroad in Google and other companies. At the same time, we should not forget Infosys and Wipro. Five engineers came together, contributed a meagre amount and started Infosys. Today, it is a milestone in the field of information technology.

While doing so, I have certain things to express very openly on this issue. When you do a public private partnership, the Government has to think very seriously about it. The education opportunities are increasing. In my days, in Mumbai, there were only two engineering colleges, one was VGTI and another was Sardar Patel Engineering College. You would not believe that. The entire State merely had five to ten engineering colleges across Maharashtra. Later on, the development took place. The education field was open and the private sector came into the education field. But, at the same time, it has created hurdle for the poor people. We have talent. Braindrain was going on. So many examples Mr. Hooda has given and other colleagues has given. Braindrain was there just because the opportunities are not there in India. It is not by virtue of job but virtue of remuneration also. Why do they go there? It is not just the opportunity but they also get a very substantial salary over there. While doing so, the Government must think very seriously. Tomorrow, the larger number of students would be coming out with B.Tech Degree, M.Tech Degree and PhD. Not only employment opportunities will have to be created but more salary also. Who is the Chief of Google now? He is Indian. The salary he is drawing there, no one can imagine in India. No corporate sector in India can pay so much of salary. What is the entire motive? It is to give opportunities and to prevent the braindrain. Are we going to get success? That has to be taken care of.

When you introduced this Bill, Prakash Ji, I heartily congratulated you in the beginning only. I feel that you must look at it because you have a very good habit of going into the intricacies of any issue. This issue also has to be dealt with that way. We should not be complacent that we have given twenty institutions of national importance. In fact, when the National Importance Bill regarding architecture was introduced, I pleaded to the Government that Sir J. J. School of Arts is one of the best colleges in the country but it was not given national importance. Kindly think of it. Such institutes are remaining out of this domain.

Once again, I congratulate you. IITs and these are people are doing good work. The Bill with a very good intention gives more and more opportunities to the students who want to go for engineering and particularly, information technology.

I purposely said about transistor. We are using mobile and everyday, there is a change. Something new develops, some new apps come or some new technology is introduced. No one thought that, on his palm, he will have a mobile in which all the apps will be there and he would see T.V. or watch the match on that. These are the things which are changing rapidly. With that speed and direction, the Government is doing well which is appreciable. I once again congratulate you for the Bill. Whatever the motive of the Government is there in this case, it should get success 100 per cent success.

15.00 hours

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

Sir, I congratulate the hon. Minister Prakash Javadekar-ji for bringing this Bill. I think it is the first time in the country that educational institutions are coming up in public-private partnership through legislation.

Sir, I have gone through all the clauses of the Bill. As mentioned in the Statement of Objects and Reasons, as per the Indian Institutes of Information Technology Act, there are four institutes – Jabalpur, Kanchipuram, Gwalior and Allahabad – and there are 15 other functional Indian Institutes of Information Technology as mentioned in the Schedule. I am unable to know from this Bill whether these 15 institutes are established through this 2014 Act or whether they are established under their own State legislations.

I am happy to note, the hon. Minister has just mentioned in his opening remarks, that the Government had decided to set up 20 new Indian Institutes of Information Technology in public-private partnership. Through this Bill, we are now going to empower these institutes to grant degrees so that the degrees can be accepted through a statute.

Other clauses of the Bill pertain to the establishment of the institutes and how they are going to function. As per the ratio, 50 per cent share is of Central Government, 35 per cent is of State Government, and 15 per cent comes from the private sector. As regards the constitution of the Board, financial and other Committees, I would like to make a suggestion. When we are thinking of private partners, they would have their own businesses. When those partners who are in the filed of technology especially and in the industry are interested to come in, I think it would be better if we see that they get a level-playing field in making decisions.

-

-

-

15.02 hours (Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

However, in this clause, we have not given them such a chance to participate in the day-to-day affairs of the institutes. Our intention is not just to get money from them because, as already mentioned, 50 per cent is put in by the Central Government, State Government puts in 35 per cent and only 15 per cent is the contribution of the private sector. That is fine. I think the intention of the Government is to let the private sector contribute to the development of these institutes through technology and new ideas.

I am happy to note, you have also mentioned it, that the reservation system will be implemented in these institutions. I think we are going to ensure it.

I am also happy to see from the Bill that you are going to give scholarships and also going to fund the institutes for the benefit of economically backward students and also meritorious students. That is a very good step. But I am unable to understand one thing and I think the hon. Minister would explain this. The hon. Minister said that he is going to spend money for recurring expenditure for a period of five years. Does that mean that these institutes should survive on their own finances after that? Does that mean that these institutes become self-sufficient after completion of five years? To what extent are they going to be supported by the Central and State Governments? I am unable to comprehend that from this legislation.

I also want to bring it to your kind notice that our State of Telangana is a newly formed State. As per the earlier Act of 2014, there is no institute in our State. The one which is mentioned in the Schedule-I was in the undivided Andhra Pradesh and now falls in the present Seemandhra Pradesh. I hope that you will permit us to submit our proposal and sanction one institute to the State of Telangana. Our hon. Chief Minister Shri K. Chandrashekhar Rao is very much interested that we get one institute in Hyderabad, which is already a centre of information technology. We do have an institute in the name of Indian Institute of Information Technology which is a successful institute in Hyderabad. We also need one institute under this new Act and I hope that you will grant one institute to our State of Telangana. I would request our Chief Minister Shri K. Chandrashekhar Rao to sanction it in my constituency Karimnagar. Thank you.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Hon. Chairperson, this is a very important Bill. I think it will have far-reaching implication in the field of higher education, particularly the engineering education in our country. The title of this Bill is the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill 2017. We established the Indian Institutes of Information Technology in 1997 with a combination of various funds. The Centre's share is 50 per cent, State's share is 35 per cent and it may be in the form of land, electricity and other means, and the industrial participation is only 15 per cent. In these institutions, we ensured reservation as per the direction given in Articles 16 and 17 of the Constitution of India. But we have elevated these institutions to the status of institute of national importance.

Institute of national importance is a status that may be conferred upon a premier public higher education institution in India by an Act of the Parliament. This is the direction of our Constitution. We established Indian Institutes of Information Technology from 1996-97. In 2017, we have started institutions under this category of IIIT. We have already given five such institutions the status of institution of national importance. Now, we are going to give 15 other institutions the status of institute of national importance. But what will happen to the right of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other reserved communities? They have got admission in the existing institutions till now but that is going to be totally abolished in these institutions. We have 23 Indian Institutes of Technology in our country. All the Indian Institutes of Technology are given the status of institute of national importance. We have more than 10,396 private engineering institutions all over the country. In Andhra Pradesh alone, there are 825 engineering institutions under the accreditation of AICTE; In Bihar, 124; in Chhattisgarh 124, in Gujarat 424, in Harayana 416, in Karnataka 756, in Maharashtra 1564, in Madhya Pradesh 556, in Tamil Nadu 1339 and in Uttar Pradesh 1165. You just go through the number of students in these institutions. There is nobody from the deprived classes. The only class you have is those who have money; only they get the admissions.

We have a number of institutions but if they convert the Government institutions into some other means, that will cut off the rare chances of

students aspiring for engineering courses. That will also be curtailed in the future. So, I strongly object to the reduction in the number of reserved seats in these institutions.

We have just gone through the situation of the Indian Institutes of Technology. We have 23 IITs. The first IIT was established in 1951 at Kharagpur; then, the IITs at Bombay, Madras, Kanpur and Delhi were established. Out of 64,432 students who are studying, a recent report which appeared in the newspaper said that in 2017 itself nine per cent drop out has happened in IITs; 886 students dropped out in 2016-17; 630, which is 71 per cent of PG students, 196 Ph.D students and 193 undergraduate students have dropped out. What is happening? Who is dropping out of IITs? They are mainly from the reserved categories.

They cannot continue their studies because of the harassment. The vacancies reserved for teaching faculty in the IITs are still not filled up; 35 per cent of these vacancies still continue in our premier engineering institutions, the Indian Institutes of Technology.

The Government is going to move their control completely and hand over these institutions to the private market. That will not help our future generation; that will not help our country; that will not help the majority of the toiling masses of this country. I request the Government to rethink and re-frame the entire Bill and give adequate representation in teaching faculty and student seats in these institutions so that we can create more engineering students and more responsible persons in the engineering field in the future.

Before I conclude my speech, I would like to say this. We produce more than eight lakh engineering students every year but the unemployment in the engineering sector is 60 per cent. I request the Government to give utmost importance to creating jobs. The Government declared at the beginning that two crore jobs would be created each year. They have completed three years but nothing has happened. I would request the Government to create jobs because in the IT sector those who have gone abroad are facing problems and have come back.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

On behalf of the Telugu Desam Party and my leader Nara Chandra Babu Naidu Garu, we fully support this Bill. For the sake of brevity, I would read a few lines from the Bill. It says:

> "A Bill to declare certain Indian Institutes of Information Technology established under public-private partnership as institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto."

We are talking about these institutions at a time when this industry is going through a major crisis. Everywhere there are retrenchments in the IT industry. The Indian IT industry is especially feeling the heat because of the firewalls being erected by America. A lot people are not going there. The H1B visas are also denied. I doubt whether these Indian Institutes of Information Technology which are intended for IT will have any future because the content of information technology always has a short shelf life. The shelf life of the software is always very short. So, people who are trained in a particular software are usually rendered jobless, under-employed or unemployed. This is the industry which generates almost 650 billion dollars. This is the industry which employs 23 lakh people directly and 2-3 crore people indirectly. Through this industry we earn a lot of foreign exchange also. But of late, the software developed by Indians as also developed all over the world is becoming obsolete, redundant and irrelevant for the present. Therefore, I am of the strong opinion, on behalf of my Party, that there should be an intensive training on the robotics or artificial intelligence. These are the areas which definitely have an edge over the routine information technology which we understand as the software development to find solutions for the existing problems. Therefore, robotics, artificial intelligence, divergent and unconventional things of IT industry should also be a part of this curriculum.

Instead of making IT industry a job seeker, let us make it as entrepreneurs so that it can provide jobs to the youth. We have a lot of expectation from the IT industry. We should always remember IT industry as a revolutionary industry. Even a villager can afford to go abroad taking his parents on flight to America and other places. It has given recognition to our country in USA. It is the IT industry which has brought laurels to the country not only in the social field but also in economy. We are earning a lot of foreign exchange in addition to direct or indirect employment opportunity. The shelf life being very short, people are becoming jobless in the software industry. Of late, a number of people are retrenched. The data of five-six mega IT industries show that as they had already recruited surplus people during the boom of the IT industry, they have now started retrenching them. Sir, through you, my request to the hon. HRD Minister would be to incorporate robotics, artificial intelligence, incubation centres in the curriculum of the software industry wherever it is coming up.

Our State, being the residual State after the process of bifurcation, is suffering a lot of financial as well as educational handicap. Thanks to the Central Government, a number of institutions have already started. They are all functional. I really thank you personally, on behalf of my Party, for taking special interest towards Andhra Pradesh. I would request you to continue showing the same interest.

In Kakinada an IIIT was inaugurated five years back. It has just stopped there only. I would request the hon. HRD Minister to look into the matter as to why this has been stopped. This can be re-started and given a new lease of life. You can have it on a PPP mode. I think it was started on PPP mode only. It somehow got buried in the layers of time. I would request you to rejuvenate it and do something to have an IIIT in Kakinada. I would request you to give top priority to new things allotted to Andhra Pradesh. Please give some academic importance to Andhra Pradesh located on the Indian map. Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity and out of turn priority because of my inconvenience.

I rise to oppose this Bill. In principle I oppose this concept of having public private partnership in higher education sector. I fully agree with the hon. Minister that it is a necessity and urgency. We have already commenced 15 IIITs. I do understand that conferring the statutory status to these educational institutions is need of the hour but in principle this mode of educational system in our country will definitely result in denying the poor, downtrodden student community the right to have the best education in IIITs.

Sir, I fully agree with the principles, aims and the objectives stated in the first part of the Bill that keeping the very significance and importance of the information technology and also the global industry in view, having quality students in the industry is the need of the hour. We know the experience in the Silicon Valley. We have also seen the experienc **e** in US regarding outsourcing and job seeking, etc. All these opportunities are there. But, the only point which I would like to make is that this IIIT should give access to the poor children belonging to BPL and the common people of this country.

I am now coming to the contents of the Bill. The very powerful Board enunciated in the Bill is the Board of Governors. Sir, I now come to Clause 3 of the Bill, that is, the Board of Governors. In Clause 3, sub-Clause (b), the 'Board' in relation to any Institute means "the Board of Governors referred to in sub-Section (1) of Section 14." Sir, this is not a pure and clear definition in Clause. Why? It is because you are saying that it is as per Clause 14 (1). Yes, I agree. Kindly see the Clause 14(1). It is very interesting to see, what is stated here is, that the constitution of the Board will be as per the Clause 14 (1). What is Clause 14(1)? It states that "the Board of Governors of each Institute shall be principal policy-making and executive body of the Institute and secondly, the Board shall consists of a Chairperson - to be nominated by the visitor of the University and recommended by the Central Government - and a nominee of the State Government and a nominee of the Central Government." These three persons are being constituted as the Board as per Clause 14(1). What about others? It is very interesting and contradicting to see that three eminent persons will be nominated by the Board. There is no Board now.

We are making a legislation. The legislation should be *pucca*. As per Clause 14(1), except the Chairman and two representatives - one representative each of the State Government and the Central Government - all others are being nominated by the Board. But, there is no Board. The Board is being given ample powers. Three eminent persons will be appointed by the Board, two eminent academicians will be appointed by the Board, including the Director and the Registrar of the Institute. Also, the policy making, the fee structure, the admission, the prospectus and all these activities are being carried out by the Board. In that Board if the nominated persons, especially the Chairman's nominated person will have ample authority to exercise. Hence, that matter has to be looked into. I think that it is not a good way of drafting the Bill.

Sir, I will conclude within a short period of time. My next point is this. This is a self-financing institute. I will elucidate. Madam and Shri Babu have stated this. I agree with this 50:35:15 ratio. But, the capital expenditure will be borne by the Government of India for five years. Subsequent to the said five years, who will finance these institutes? Definitely, it will be a self-financing institute. What is the fate of the self-financing institute? I can share my experience in my State. In my State, we have started self-financing colleges and engineering colleges are started like anything. All the cashew industries, blade mafia and everybody have started engineering colleges. Now, the hon. High Court has come to a verdict that most of the colleges have a result of less than 10 per cent and the entire higher education scenario is in peril. So, my point here is that who will finance after five years? You have to find the resources within the organisation. That means the fees will be very high and the poor children or the poor students will not be able to afford the fee structure. It shows that these self-financing institutions will also be for the elite students of the community.

That is why I am saying that, in principle, I am opposing it. The first Board of Governing Body will be notified. What about the second Governing Body? It is the creation of the Parliament. The hon. Minister may kindly see. We are creating a Statute. By virtue of that Statute, we are making an institute. The Parliament has a right to know as to who all constitute the Board of the Governors. You will notify the first body. If you will notify it, definitely it will come to Parliament. But if you are not notifying in subsequent cases, it need not come to Parliament. Since it is the creation of Parliament, my suggestion and submission to the hon. Minister is that definitely the subsequent constitution of the Board of Governors should also be notified and the notification should come to Parliament so that the Parliament will get the awareness of what is happening in the IIITs in the country.

In principle, I want to oppose this Bill. With these words, I conclude my speech.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Sir, I thank you for giving me this opportunity

Through this Bill certain Indian Institutes of Information Technology established under public-private partnership are proposed to be declared as Institutions of national importance. The main objective is to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards.

These IIITs are being empowered to award degrees. This promotes autonomy and develops spirit of competition among the peer institutions thereby raising academic standards. This is a very welcome step. This measure will certainly attract good students which will help in developing a strong research base in the field of information technology.

This will enhance the prospects of the graduating students in the job market. I welcome the government's decision to set up an IIIT In Andhra Pradesh. Well-equipped infrastructure will play a major role in attracting and retaining good faculty and would also enable the students to exploit their potential to the highest standards. The autonomy provided to develop its own academic programmes including curriculum, new courses and method of assessment will help in meeting the student aspirations and. industry requirements.

The results of such research needs to be implemented across all layers of society and the benefits be made accessible to the large population of this country. The essential requirement of the proposed IIITs should be the availability of quality faculty and incubation of research. The number of Ph.Ds produced in India is small when compared to the vast population. India is the world's largest sourcing destination for the information

technology (IT) industry, accounting approximately 67 per cent of US $ 124-130 billion market. The industry employs about 10 million workforce. The industry has led the economic transformation of the country and altered the perception of India in the global economy.

India's cost competitiveness in providing IT services, which is approximately 3-4 times cheaper when compared to developed countries and is the unique selling proposition in the global sourcing market. India is also gaining prominence in terms of intellectual's capital with several global IT firms setting up their innovation centres in the country. The computer software and hardware sectors in India attracted cumulative foreign direct investment (FDI) in-flows worth US $ 2283 billion market between April 2000 and December 2016.

India is the topmost offshore destination for IT companies across the world. In view of the recent initiatives taken by US and certain other countries, our IT industry is getting affected and thereby many of our software professionals' jobs are at risk. I may incidentally mention that majority of these professionals belong to the Telugu States. I request the government to take steps to address the concerns of IT industry by taking up the issue with appropriate authorities.

Though we have made progress in setting up institutions of higher learning they are not able to cope up with the growing population. However, to be able to lift a population of 450 million out of poverty and to have them participate in the country's economic development, higher education needs to be a priority. This is where these kinds of institutions could have an increasingly important role. We need to set up more number of similar institutions to cater to the growing population.

In this connection, I would like to make a humble submission for the consideration of this Government. One is to provide 30 per cent reservation to women in admissions to IIITs. As it is we are having a lot of women leaders heading large organisations in India and some abroad. Providing reservation to women will create a pool of women management professionals.

I also request the Government to speed up the process of setting up the IIIT in Kurnool.

I welcome this Bill whole-heartedly as this will promote and strengthen technical education in our country.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Chairman Sir, I had requested earlier to take up the subject of kisans. Now the discussion on the Bill is going on. The discussion on the Bill can be postponed to tomorrow and the subject of kisans may be taken up now.â€¦ (*Interruptions*) Earlier you told that only four or five Members will speak and now, everybody wants to speak on the Bill. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The reply will be given at 4 p.m.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): We said that discussion will start at 3 p.m. ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Shri Javadekar is very accommodative. He will agree with our proposal.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Shri Kharge, please wait for half-an-hour and then, we will discuss the subject of kisans.

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Mr. Chairman Sir, I congratulate the hon. Prime Minister and the Minister for HRD, Shri Javadekar for introducing the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017.

Sir, today knowledge is power. I am very proud that I am coming from Karnataka where the famous engineer, Shri M. Visvesvaraya has contributed much for the country's development since before Independence in the field of technology. I am proud to say that the Visvesvaraya Technological University is there in my own constituency which caters to the needs of entire Karnataka and every year, many engineering graduates are passing out from that University.

Today it is one of the famous institutes. It was a self-financing institute under the State Government. Unfortunately, during the UPA Government, an income tax raid had taken place in that University. It was being self-financed. ...(*Interruptions*) You know very well that only during your Government, income tax raid had taken place and about Rs. 500 crore has been taken from that University by the Central Government.

Now we are going in for public-private partnership. I request the Minister for HRD and the hon. Finance Minister to look into the grievances of the University which were there during the UPA Government. I request them to set things right for that University which is one of the best Universities in the country today.

I request Shri Javadekar and Shri Arun Jaitley to come to the rescue of the University and look into the mistakes done during the UPA Government.

Many Members said that engineering students should not become job seekers. Shri Visvesvaraya had said: "industrialise or perish". Today, when most of the engineering students take admissions, they aspire for Government jobs. They should not become job seekers; they should become job creators.

I was in Korea a few days back. It is a very small country. They got Independence on 15th August, 1947 like how India got Independence in 1947. But a small country like Korea has been manufacturing mobile phones, Hyundai cars and other things and they are supplying them to the entire world. My concern is, our engineers should not depend only on jobs.

Under the hon. Prime Minister's dream initiative of 'Make in India' plenty of opportunities are available for engineers today. So, they should go for manufacturing sector. There are chances for manufacturing in many areas, like aerospace. In my State, our people are manufacturing helicopters, aeroplanes, etc. There are other areas like naval base, agriculture and food processing which offer plenty of opportunities for the engineers. The basket is full of opportunities. Those should be utilised.

Once upon a time, Obama said, 'No to Bengaluru, yes to Buffalo'. Then, many students came back from America. Then, after six months, during the

UPA regime itself, Dr. Manmohan Singh made a request. Then, Obama said, 'we are depending on Bengaluru also and not only on Buffalo'. It is because the talent and the knowledge of the Indian youth are very high. But we are not giving them enough opportunities or a proper platform to make use of their talent.

Today Shri Narendra Modi and Shri Javadekar, hon. Minister of Human Resource Development have provided that platform to these engineers. These engineers should help in further development of the country's economic progress. Already 'Digital India' has come into being. During demonetisation, most of the people utilised digital money through cards, etc. Today, the whole country requires many engineers who should teach our youngsters and elders about the digital financial transactions. In our country itself much more manpower is required in the IT industry. Many banks and institutes want to make their operations paperless. For this we can utilise the services of these engineers.

So, the arrangement should be made by the respective State Government and the Central Government in this regard so that we can save a lot of money and a lot of energy. This technology can be utilised for the development of the country. Imagine how much money we have to spend for printing currency notes. If you implement digitisation, employment opportunities can be created for the youth.

On the initiative of the hon. Prime Minister and the HRD Minister, these 15 institutes are being given statutory status, which produce the best of engineers. I am very proud to say that the Indian Institute of Science which is in my State is the only Institute that has found a place in the list of first 100 universities of the world.

Teaching is a noble profession. Teaching is a choice and not a chance. I would request the teaching fraternity to dedicate their services for the teaching purpose. Today most of the teachers are not interested in teaching. They are interested only in the salary part. Earlier we had teachers like Dr. Visvesvaraya and Dr. Radhakrishnan, the former President. Teaching, as I said, is a noble job. So, I would request the teachers and teaching fraternity to dedicate their time and services for imparting knowledge to our youngsters.

I once again congratulate the hon. Prime Minister and the HRD Minister for introducing a Bill relating to IIITs. These 15 Institutes should be recognised at the world level for their excellence. They should give better service to India and to the world. May God bless all these students and the youngsters in the coming days!

I support the Bill. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह संशोधन विधेयक उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कौशल विकास को मानव संसाधन से जोड़कर हमें सबको आगे बढ़ने का अवसर देना है। इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के साथ जोड़ना है और प्रोत्साहित करना है। इसमें विकलांग से लेकर गरीब लोगों को मौका देना है।

आईआईआईटीज को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। कुशल कामगार, स्किल और श्रमिक ही देश की जान और प्राण हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को ये ही बचाएंगे। जापान में डिग्री का महत्व नहीं है, स्किल-नॉलेज का महत्व है। हमें भी स्किल-नॉलेज को बढ़ावा देना है, डिग्री को महत्व नहीं देना है। राज्य, केन्द्र और प्राइवेट सेक्टर को जोड़कर हमें इसे आगे बढ़ाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, गरीबों को अवसर देना है। समाज के गरीब, दलित, शोÂिषत, उपेक्षित, वंचित और लाचार वर्गों को ज्यादा मौका देना चाहिए। हमारे देश के लोग अमेरिका एवं अन्य देशों में जाते हैं और अपने हुनर दिखाते हैं। इसमें बैंकिंग सुविधा भी मिलनी चाहिए। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए हम आईआईआईटीज को जितना बढ़ावा देंगे, उतना अच्छा होगा। अभी किसान के मामले पर बहस शुरू होगी, इस देश में आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, हमारे एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय जावड़ेकर जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) बिल, 2017 इंट्रोड्यूस किया है। मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूं।

सभापति जी, 7 दिसम्बर, 2010 को यूनियन कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें बीस ऐसे आईआईआईटीज पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू करने का एलान किया गया था, लेकिन उनमें केवल 15 आईआईआईटीज शुरू हुए और उनको भी अभी तक डिग्री ग्रांट करने की पावर नहीं थी। मेरे ख्याल से इस बिल में उसके लिए प्रॉविजन है, इसलिए मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा। 12 दिसम्बर, 2015 को एचआरडी मिनिस्टर ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें तीन नए इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रावधान किया गया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं और आप जानते हैं कि कोल्हापुर एक बहुत ही प्रॉसपरस प्लेस है। यहां के लोग मेहनती हैं और उनमें हुनर है। मैं चाहूंगा कि कोल्हापुर में भी ऐसी एक आईआईआईटी खोली जाए। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी को एआईसीटीई ने थर्ड रैंक दी हुई है। कोल्हापुर के आस-पास लगभग 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, आईटी और आईआईटीज के तकरीबन 150 यूनिट्स हैं, 350 हार्डवेयर यूनिट्स हैं और वहां 3000 से ज्यादा लोगों को इम्प्लायमेंट मिला हुआ है। कोल्हापुर म्युनिसपल कारपोरेशन ने एक आईटी पार्क की घोषणा की है, जिसमें 4000 से 5000 लोगों को इम्प्लायमेंट मिल सकता है। इस तरह से यह शहर दक्षिणी महाराष्ट्र का एक आईटी हब बन सकता है। जैसे दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर का प्रस्ताव है, उसी तरह से मुंबई-बैंगलोर कॉरीडोर का भी आपने प्रॉविजन किया है। उसमें भी इस इंस्टीट्यूट से बहुत मदद हो सकती है। आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे यहां पढ़ते हैं और उनको पूना, मुंबई और बैंगलोर में जॉब के लिए जाना पड़ता है।

अगर कोल्हापुर में ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनता है तो अच्छा होगा। आप जानते हैं कि कोल्हापुर एक इंडस्ट्रियल हब भी है, वहां पर किर्लोस्कर, रेमण्ड जैसी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर वहां पर ऐसा एक इंस्टीट्यूट खुलेगा तो अन्य 20 हजार से 25 हजार लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो सकती है। आपकी सरकार का नारा था और चुनाव से पहले आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पांच साल में दो करोड़ से ज्यादा लोगों को जॉब दी जाएगी। मेरे ख्याल से इस इंस्टीट्यूट से उसमें मदद हो सकती है। कोल्हापुर में यह इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हम इंट्रेस्टेड हैं, कृपया आप इस पर विचार करें। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, धन्यवाद। एक बेहद जरूरी बिल, जो शायद आईआईआईटीज को एक नए लेवल पर ले जाने का काम करेगा, आज इस सदन में आया है - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) बिल, 2017। इस बिल में जो दो-चार अहम चीजें हैं, जिनके बारे में देश जानना चाहता है, उनके बारे में, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना भी चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। आज इस बिल में बड़े गंभीर तरीके से सरकार ने बताया है कि खर्च का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 35 प्रतिशत राज्य सरकार और 15 प्रतिशत इंडस्ट्री पार्टनर्स देंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे 20 सेट-अप किए जायेंगे। हमने पहले भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं और आज यह हालत है कि देश के उन इंस्टीट्यूट्स में भी पूरी तरह फैकल्टी प्राप्त नहीं है।

आज हम ट्यूशन-फी की बात करते हैं तो जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वे किसान के बेटे हों या किसी ऐसे मजदूर का बेटा हो, जो आज टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आज उनकी जेब की हालत यह नहीं है कि वे एक लाख रुपया या सवा लाख रुपया फीस दे पायेंगे। क्या सरकार इन इंस्टीट्यूट्स में ऐसे प्रावधान करेगी, जिसके तहत गरीब बच्चे भी इन इंडस्ट्रीज सपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पायें?

दूसरी चीज यह है कि सरकार द्वारा कहा गया है कि इस बिल के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी लैंड, इन सभी की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट देगी। आज यह हालात है कि जो इन्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, मैं अपने ही लोक सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाल कर वेटनरी की यूनिवर्सिटी बनायी गयी है, आज तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के लिए सरकार ने एक रुपया देने का काम नहीं किया है। अगर हम देश में ऐसे 20 और इंस्टीट्यूट्स बनाने का काम करते हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स किस मॉडल से लाने का काम करेंगे, जबकि 35 प्रतिशत हिस्सा सरकार डालेगी।

माननीय एचआरडी मिनिस्टर द्वारा ही हरियाणा के अंदर एक हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गयी है। केन्द्र सरकार को उस घोषणा को किए हुए आज ढ़ाई साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अगर हम इस तरह की घोषणा करते रहेंगे तो किस वर्ष तक हमें इंस्टीट्यूट्स धरातल पर बनते हुए दिखेंगे।

15.46 hours

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

मैं आखिरी चीज माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब हम आईआईआईटीज की बात करते हैं, यह आने वाले जमाने की टेक्नोलॉजी का बहुत अहम् हिस्सा है। जिस फेज मैनर में इन इंस्टीट्यूट्स को डेवेलप किया जा रहा है, जब तक ये इंस्टीट्यूट्स बनेंगे तो शायद आज इन इंस्टीट्यूट्स में जो टेक्नोलॉजी लगाने का काम करेंगे, तब तक वह फेज आउट हो जायेगा। क्या आप इंक्यूबेशन का सिस्टम लायेंगे, क्या इन इंस्टीट्यूट्स को टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली डेवेलप करने के लिए मॉडर्नाइज करेंगे? जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज इसमें 15 प्रतिशत हिस्सा डालेंगे, क्या उनको फोर्स किया जायेगा कि वे टेक्नोलॉजी डेवेलप करें? क्योंकि आज आप चाइना, इंगलैंड और यूएसए को देखते हैं, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी इजरायल गये, वहां छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट्स ने बड़े-बड़े टेक्नोलॉजिकल इंवेशंस की हैं। क्या इन इंस्टीट्यूट्स को उस मॉडल पर डेवेलप किया जायेगा? इसके लिए बहुत जरूरी कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो अहम कदम बिल में उठाने चाहिए, आप आने वाले समय में उनको भी अमेंडमेंट के माध्यम से डालने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में संसाधन सीमित हैं। सरकार इस क्षेत्र में ज्यादा खर्चा भी नहीं कर रही है। इस कारण हमारी जनसंख्या एवं जरूरत को सही ढंग से पूरा नहीं कर पा रही है। इस परिस्थिति में प्राइवेट लोगों की भागीदारी अनिवार्य है, जिससे कि आज की आवश्यकता के अनुरूप अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। अभी चार संस्थान जबलपुर, कांचीपुरम, ग्वालियर और इलाहाबाद में स्थापित हैं। ये पूर्णतः सरकार के अधीन हैं। 15 संस्थान पीपीटी में संचालित हैं, किंतु पूरे देश में इनकी संख्या और अधिक होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं। वहां लगभग 11 करोड़ की आबादी है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में मात्र एक संस्थान की मंजूरी मिली थी। राज्य सरकार ने भागलपुर इंजीनियरिंग कालेज के साथ 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता अलग से करा दी है। उसकी स्थापना के लगभग सात वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2017-18 में पहले बैच का नामांकन होना है, जिसमें मात्र दो विषयों की पढ़ाई होगी। इसमें मात्र 60-60 बच्चे ही लिए गए हैं। माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहां राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन-तीन सौ बच्चों के नामांकन को मंजूरी दी जाए और वहां चार विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए, जिससे बिहार के बच्चे, बिहार की मेधा आगे आ सके। आप देख सकते हैं कि देश में जितने भी इंजीनियरिंग कालेज हैं या अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां बिहार के बच्चे पहुंच रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बिहार के तीन-तीन सौ बच्चों को नामांकन की सुविधा मिले। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस कम होनी चाहिए, दलितों के बच्चों के लिए फीस कम होनी चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था करने की कृपा करें।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Sir. I rise to support the Bill. I would also like to state that this particular addition of this PPP mode in the Indian Institutes of Information Technology is adding to the overall eco-system of information technology and software services in our country and also the capability for building human capital that is required in the 21st century. It is very very important. Having said that, the national importance that we are giving to it is in the form of not only just the recognition but also in terms of aligning with the markets through the private partnership route. This is a very very important thing because what is happening in the marketing is something that we need to keep an eye on.

Today only, I had tweeted about a particular drone that is available today and which can plant one lakh trees per day. Such things like drones, robotics and whichever my learned friends had said earlier about artificial intelligence, deep learning, etc., are the things that will be happening in the future. More and more of the coding that is going to happen is going to be driven by artificial intelligence and by machines.

Therefore, in order for us to get the best out of our human capital, I believe that the Indian Institutes of Information Technology must also think in terms of social sciences so that there is holistic learning. In a country like ours, we cannot leave the social sciences to just chance. Therefore, I would say to the hon. Minister that it is time to do that. We also had given national importance to some of the best institutions which are giving liberal education and social sciences.

I would like to end by saying one final point. In the North-Eastern States, the investment ratio today is at 57.5 by the Central Government, 35 per cent by the State Government and 7.5 per cent by the private entity. We would request that

this be changed to 82.5 per cent from the Central Government, 10 per cent from the State Government and 7.5 per cent from the private entity. This is because the North-Eastern States till today do not have any Indian Institutes of Information and Technology. I hope that the first one will come up

in the State of Sikkim.

Thank you very much.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I am happy to participate in the debate on the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017, established under public-private partnership with the global standards.

I am coming straightaway to the point. Here, specifically, we are emphasizing on the private participation. We would like to know from the Government as to what is the role of the private institutions which are involved in it. What is their role? It is because at the time of formation of this public-private participation, these institutions had come in by mere force. They had to invest about Rs. 19 crore in three institutions together. The Government of India should define exactly as to what is the role of these private institutions. What benefits will they get? In what way we will be benefited by their participation?

Secondly, as was said, 50:35:15 is the stake: 50 per cent is of the Central Government and 35 per cent is of the State Government. That means, it will come to about Rs. 44 crore out of Rs. 128 crore. But, as one of my colleagues, Shri Ramachandran said, about 50 acres of land has to be provided by the State Government. It will cost you about Rs. 50 crore. That means, about Rs. 94 crore will be given by the State Government. In other words, the stake of the State Government will be much higher than that of the Central Government. So my request to the Central Government is that either it should increase the stake of the Central Government from Rs. 64 crore – that is 50 per cent of Rs. 128 crore – to a higher amount or it should reduce the stake of the State Government.

I would like to put forth one more point. In the recent scenario, thousands of IT graduates are jobless. They are not placed in good institutions. Moreover, we find that they are migrating from the State or they are going abroad. Probably, in the same institution, in the same vicinity or in the same campus, you can have

an info park or a techno park so that we can have on-the-job training. We can have placement also in the same place. Of course, we can have a startup village also along with the Indian Institute of Information Technology.

These are the things I would like to say. The other things have already been said by my colleagues. Due to paucity of time, I would not like to elaborate them. Thank you very much.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी (पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप) बिल, 2017 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, इस बिल को हम चार टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला, जो इंस्टीट्युट हैं, उनको नैशनल इम्पोर्टेंस देना है। दूसरा, यह बिल पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप में इंस्टीट्युट्स को बनाने की अनुमति प्रदान करता है। तीसरा, यदि हम इसके ऑब्जैक्ट्स की तरफ देखें, तो यह बिल इन इंस्टीट्युट्स के माध्यम से नये ज्ञान के स्रोत खड़े करने के लिए काम करता है। चौथा, इंडस्ट्री की जो ग्लोबली रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप मैन-पावर को तैयार करने की दिशा में काम करता है। यदि हम इन चारों ऑब्जैक्ट्स को देखें, तो विश्व के अन्य विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, ठीक उसी तरह की व्यवस्था, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एप्रोच है- एक नया भारत बनाने की, उसी तरह की व्यवस्था को भारत में स्थापित करने की दिशा में यह काम करता है। ऐसा महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और इनका अभिनन्दन करता हूँ।

देश में ह्युमैन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा फण्डेड पाँच आई.आई.आई.टीज काम करती हैं। इसके अतिरिक्त पी.पी.पी. मॉडल पर 18 नये इंस्टीट्युट्स स्थापित करने की बात है। यदि हम देश भर के एजुकेशन इंस्टीट्युट्स की रैंकिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने वाले, उनकी रैंकिंग का डेटा रखने वाले इंस्टीट्युट्स के दृष्टिकोण से बात करें, तो जिस किसी इंस्टीट्युट्स को नैशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला है, उनकी रैंकिंग्स एलिवेट हुई हैं, उनकी रैंकिंग्स ऊपर बढ़ी हैं। जिन इंस्टीट्युट्स की रैंकिंग ऊपर बढ़ी है, उनका इम्प्लॉयबिलिटी रेशियो भी बढ़ा है। यदि देश की इंजीनियरिंग कॉलेज के दृष्टि से मैं बात करूँ तो देश में कुल इंजीनियरिंग कॉलेजेज में से सबसे ज्यादा तमिलनाडु और महाराÂष्ट्र में हैं। लेकिन इम्प्लॉयबिलिटी की दÂिष्ट से बात करूँ तो उन दोनों स्टेट्स की इंजीनियरिंग कॉलेजेज की इम्प्लॉयबिलिटी रेशियो सबसे कम है।

16.00 hours

इस दÂिष्टकोण से हम देखें, यदि हमें इम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि आज भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज से जितने इंजीनियर्स पास-आऊट होते हैं, उनकी इम्प्लॉयबिलिटी केवल 3.84 पर्सेंट है। जबकि, जो 50 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, आई.आई.टीज़. या सरकार ने जो इंस्टीट्यूट्स ट्रिपल आई.टीज. के रूप में बनाए हैं, यदि हम उनकी एम्प्लॉयबिलटी को देखें तो वह 30 परसेंट तक है। नेश्नल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स बनने से देश में एम्प्लॉयबिलटी बढ़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। यदि मैं इस दृष्टिकोण से बात करूँ कि आज पूरे विश्व में जिस तरह का चलन है, इस प्रवलन के अनुरूप एकेडमी और इंडस्ट्री, दोनों

एक साथ पैरलल खड़े होकर काम करते हैं और इसके कारण जिस तरह की आवश्यकता इंडस्ट्रीज़ को है, उस तरह का एम्प्लॉई उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तैयार होता है। यदि मैं हमारे देश की चार टॉप आई.टी. कंपनीज़ की बात करूँ तो वह साल भर में लगभग 1,723 करोड़ रुपये ट्रेनिंग पर खर्च करती हैं। ट्रेनिंग पर होने वाला यह खर्चा इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से होगा तो स्टूडेंट का ट्रेनिंग में एजुकेशन के बाद 6 महीने या एक साल का जो समय व्यर्थ होता है, उससे समय की बचत हो सकेगी। इससे इंडस्ट्रीज़ अपनी रिक्वायरमेन्ट के लिए कस्टोमाइज़्ड रूप से स्टूडेंट्स तैयार कर सकेगी। इसके कारण स्टूडेंट के भी 6 महीने या एक साल के समय की बचत होगी। इससे इंडस्ट्री का भी पैसा और समय बचेगा। इस दÂिष्टकोण से यह बिल अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I do subscribe to the views enshrined in the legislative document, that is, in the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017. Actually, it was initiated in the year 2010 under the UPA regime. Sir, I would simply ask two or three queries to our hon. Minister Javadekar Ji.

Javadekar Ji, the Bill is silent whether the institute will have to implement reservation for SC, ST and OBC in faculty recruitment. That needs to be clarified. Once we conjure of the information technology, suddenly the name of Rajiv Gandhi Ji will certainly come up who has initiated and who has waged the information revolution in our country and that is why, now, India has been recognized as an information technology super power across the world.

सर, एक जमाना था जब यदि किसी के पास मोबाइल होता था, तो हम उसे रईस आदमी कहते थे, लेकिन अब हर आदमी की जेब में मोबाइल आ गया है। आज ब्राह्मण के पास भी मोबाइल है और चंदेल के पास भी मोबाइल है। आज हरिजन के पास भी मोबाइल है और अमीर के पास भी मोबाइल है। आज प्रधान मंत्री जी के पास भी मोबाइल है और प्रधान मंत्री जी के संतरी के पास भी मोबाइल है। हिन्दुस्तान में आज यह देखने की सब से बड़ी चीज़ है।

Sir, I would simply draw the attention of the hon. Minister that out of 15 lakh engineering graduates coming out every year, just about 10 per cent graduates are employable – a euphemism for their non-trainability. In other words, about 90 per cent of them after about 3-5 hours of study, standing across four years of their course, remain largely below par for the purpose they were originally admitted.

McKinsey Report published some three months ago made another startling revelation. By 2025, less than a decade from now, as many as 14 lakh middle level work force in IT industry accounting for 45 per cent of the total work force as of

now will face an uncertain future in an era of fast moving changes brought about by digital fire forces and the resultant adoption of automation in a big way.

जावड़ेकर जी, आप तो एच-1 वीज़ा का चक्कर जानते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में एंटी-आउटसोर्सिंग की लड़ाई चल रही है। इस हालत को देखते हुए आपको नई सोच लानी पड़ेगी। यदि आप इसी ढंग से चलेंगे, तो काम नहीं चलेगा।

I would like to draw your attention to another thing that even we have established the Mecca of Information Technology in Bengaluru which has goaded Barack Obama to say that now on the job has been *Bengalured*. So, that kind of kudos we have already earned. I would quote our outgoing President, one of the greatest parliamentarians in the history of India, Shri Pranab Mukherjee.

> "Education is power. It provides knowledge, which provides development and in today's world the higher educational system has great importance in building a society. When you talk of power, it is not only the number of soldiers and number of weapons but behind this, better technology which comes from a great educational system which empowers individual and the society. On the one hand we require access to higher education, we must have expansion of educational intellectual component creating many more institutes of higher learning and higher education but mindless enhancement of educational institutes without taking due care of its intellectual component on quality of education, would not be worth pursuing. "

Thank you Sir.

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सार्वजनिक निजी साझेदारी आई.आई.आई.टी. (पी.पी.पी.) विधेयक, 2017 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन्होंने यह कल्पना की कि देश की आवश्यकताओं देखते हुए वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृष्टि की मांग को देखते हुए 20 आई.आई.आई.टी. पी.पी.पी. मोड पर खोले जाएं। उसमें से 15 इतने कम समय में फंक्शन में आ गए हैं। वहां अध्ययन-अध्यापन शुरू हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हर आई.आई.आई.टी की लागत 128 करोड़ रुपये रखी गयी है। यह आ गया है। यह भी है कि इसको पी.पी.पी. मोड पर रखा गया है और हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की मांग और हमारी शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटने का काम इस विधेयक द्वारा किया जाएगा। हमारे दूरदर्शी और कल्पनाशील प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुपर पॉवर बनने की दिशा में अग्रसर है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और आज की अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था है। हमारा देश विकासशील देश है, लेकिन विकासशील और विकसित देशों का जो अंतर है, वह प्राकृतिक संसाधनों का अंतर नहीं है, वह देश की सीमाओं का अंतर नहीं है, वह देश के लोगों का भी अंतर नहीं है। वह अंतर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। आज अगर छोटे देश भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे हैं तो वे विकसित देश हैं और बड़े से बड़े देश भी प्रचुर संसाधनों के होते हुए भी अगर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वे विकासशील देश हैं। हमारे कल्पनाशील प्रधान मंत्री ने देश को विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया है। निश्चित रूप से यह उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में सुधार ला सकेगी, हमारी जनता को, हमारी बड़ी आबादी को रोटी, कपड़ा और मकान दे सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मेक इन इण्डिया जिस गति से विकास कर रहा है। उसी गति और उसी गुणवत्ता के लिए हमें तकनीशियन चाहिए, जो इस तरह के संस्थान हमें दे सकेंगे। देश में पहला मौका है जब एक साथ 15 संस्थान खड़े किए गए हैं। अभी कांग्रेस के हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने बड़ा काम किया। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सन् 1961 में मुम्बई में पांचवा आई.आई.टी. खुला था और उसके बाद सीधे सन् 1994 में में खुला। इसका मतलब यह है कि 31 साल तक एक भी आई.आई.टी. इस देश में नहीं खुला। इसमें राजीव गांधी जी की भी सरकार थी। कांग्रेस जितनी योजनाएं लायी, वे चाहे मनरेगा हो, या फूड सिक्योरिटी बिल हो। आज भी वे किसानों के लिए यह कर रहे हैं। लेकिन देश में परिवर्तनकारी किसी भी कदम के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हुई है। देश को यथास्थिति में रखने का काम, सारा दर्शन का कांग्रेस का इसी आधार पर है। 31 साल तक एक भी आई.आई.टी. नहीं खुली हमने केवल 3 सालों में 20

आई.आई.आई.टी. इस देश को दिए और इन्होंने 60 सालों में केवल 16 आई.आई.टी. दिए। यह बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार और इनकी सरकार का अंतर है, यह दर्शन का अंतर है। आज भारत विश्व में महाशक्ति बना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर हमने ध्यान दिया है। आज उपग्रह के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा भारी उपग्रह ले जा सकते हैं। पहले उपग्रह का वजन 3200 से ज्यादा किलोग्राम का वजन होता था। हमें दूसरे प्रक्षेपण लेने पड़ते थे। आज हमने इण्डीजीनस टेक्नोलॉजी से 10 हजार किलोग्राम तक पहुंचाने का काम किया। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारा देश केवल इस दिशा में आगे बढ़ सकेगा। आज विश्व प्रक्षेपण का मार्केट 14 लाख करोड़ रुपये का है। उसमें से 41 प्रतिशत की भागीदारी केवल अमेरिका की है। हमारा इतना संसाधन विकसित होने के बाद भी उसमें केवल 4 प्रतिशत भागीदारी है। अगर हम इस क्षेत्र में विकास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की गरीबी को दूर करने का एक माध्यम बनेगा।

मैं जानता हूं कि कांग्रेस किसानों पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक है। जब महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी। जब कांग्रेस शासित राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब कांग्रेस चुप थी।...(व्यवधान) मैं केवल तीन-चार बिंदुओं में अपनी बात करूंगा। मेरे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वे रिसर्च ओरिएण्टेड नहीं हैं। हमारे जो संसाधन बन रहे हैं, यदि हम इन्हें रिसर्च ओरिएण्टेड रखेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए उपयोगी होगा।

एक पक्ष यह भी है कि सन् 1951 में जब पहला आई.आई.टी. बना, उसके बाद 1953 में पहला आई.आईटियन निकला, उसके बाद से आज तक करीब 25 हजार आई.आईटियन हमारी पूर्ववर्ती सरकार और कांग्रेस की नीतियों के कारण देश छोड़कर विदेशों में चले गये। अब जो आई.आईटियन बन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी क्लाज डाली जाए कि जिससे कम से कम 10 या 15 साल इस देश की सेवा आई.आईटियन को करनी पड़े, तब वे विदेश में जा सकेंगे तथा साथ ही एक ऐसा बांड भरवाना चाहिए कि वे इस देश की सेवा कर सकें। अभी जो 24 संस्थान हैं, इन्हें देश की रक्षा के लिए और सामरिक संप्रभुता के लिए डीआरडीओ, इसरो तथा अन्य संस्थानों से जोड़ा जाना चाहिए, तभी इन संस्थानों का लाभ मिल पायेगा।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे उज्जैन नगर में पानी, जमीन और अन्य सभी चीजें उपलब्ध हैं, वहां सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। अगर इस तरह के रक्षा के संस्थान हमारे उज्जैन में भी स्थापित किये जायेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आई.टी. क्षेत्र में हमारे देश का विश्व में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया भर में बहुत बड़ी-बड़ी आई.टी. कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अमेरिका में जो बोइंग कंपनी जहाज बनाती हैं, उसमें सैकड़ों इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और टैक्नीशियंस सिर्फ गुरूनानक देव इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना के हैं। बोइंग में जी.एन.ई. के बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं। ऐसा ही माइक्रोसोफ्ट में है और ऐसा ही गूगल में है। मैं क्योंकि पंजाब को रिप्रजैन्ट करता हूं, यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पंजाब में इंजीनियरिंग कालेज बहुत हैं, लेकिन प्लेसमैन्ट के लिए पंजाब के स्टूडेंट्स को पुणे, बंगलुरू, हैदराबाद या गुरुग्राम जाना पड़ता है। पंजाब में भी आई.टी. हब बन सकता है। अगर मोहाली में बने तो चार-पांच स्टेट्स इसमें कवर हो सकती हैं। मंत्री जी इसका एरिया यदि पंजाब में कहीं भी चुने तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं। मैं यह चाहूंगा कि पंजाब में जो इंजीनियरिंग कालेजिज के स्टूडेंट्स हैं, जैसा मेरे से पहले हमारे कुलीग्स ने बोला है कि हजारों की संख्या में इंजीनियर्स ब्रेन ड्रेन होकर विदेशों में जाते हैं। अब विदेशों में भी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे अमेरिका ने एच-1 वीजा में कड़े प्रावधान लगा दिये हैं, उससे भारतीय इंजीनियर्स प्रभावित होंगे।

इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि पंजाब को एक आई.टी. हब दी जाए, क्योंकि पंजाब वह स्टेट है, जिसने देश की आजादी में 90 प्रतिशत से ज्यादा कुर्बानियां दी, जिसने हरित क्रांति के जरिये अनाज के मामले में पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज अगर पंजाब के स्टूडेंट्स की प्लेसमैन्ट यहीं पर होती है तो उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली सरकार ने अमृतसर में एक इंफोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी पार्क दिया था, लेकिन वह अनाउंसमैन्ट से आगे नहीं बढ़ पाया। सिर्फ नींव का पत्थर रखने से या चर्चा करने से काम नहीं होगा, इसको अमली रूप दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि हम हर बात पर आलोचना नहीं करते, We are not critic just by habit, we also praise if you deserve it. सरकार ने जो अच्छे कदम उठाये हैं, उनकी हम सराहना भी करते हैं। भारत के जो अच्छे-अच्छे दिमाग हैं, उनका ब्रेन ड्रेन न हो, वे बाहर न जा पायें, वे देश की सेवा में लगें। यही मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने पचास से सौ एकड़ जमीन का जो प्रावधान रखा है, जब नवोदय विद्यालय और सैंट्रल स्कूल के लिए सरकार कोई जमीन नहीं दे पाती है, क्योंकि इतनी सारी जमीन आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो जो कहावत है - 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।' जमीन अब इस देश में नहीं है, इसलिए आप इस जमीन की रिक्वायरमैन्ट को कम करिये। इतनी जमीन कहां से देंगे, बंजर भूमि की स्थिति में झगड़ा है और आप देख रहे हैं कि जल, जंगल और जमीन के मामले में देश की क्या स्थिति है। पहली बात यह है कि यह जमीन बहुत ज्यादा है, आप इसे कम करिये।

दूसरी बात आपने इसमें लिंग, जाति, धर्म, विक्लांग, निवास आदि नई चीजों का जो समायोजन किया है, निश्चित रूप से यह बहुत बेहतरीन है। हम बिल के समर्थन में हैं लेकिन आपने इसमें जो प्राइवेट सैक्टर को लिया है, जब आप इसमें प्राइवेट सैक्टर का पैसा लगायेंगे, खुद करोड़ों-करोड़ रुपये लगायेंगे। आपने विक्लांग को दे दिया, अन्य लोगों को दे दिया तो गरीब आदमी उस स्कूल में कैसे जायेगा। जब फीस एक लाख पच्चीस हज़ार रूपये होगी गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भाÂषण तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपने जो किया वह सही नहीं है। मध्यवर्गीय बच्चों को, मेधावी बच्चों को फीस में छूट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मेधावी बच्चे कौन होते हैं? ये पूंजीपति और बड़े-बड़े लोगों के बेटे बहुत मेधावी नहीं होते हैं। इस हिंदुस्तान में मेधावी जो है, वह रिक्शा चलाने वाला है, टमटम चलाने वाला है, जो मज़दूर है, जो काम करता है, अभाव में जीता है, जो वंचित है, उमसें जो टैलेंट है, वह दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब तक आप उस टैलेंट के व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक आपने आईआईआईटी के बारे में जो बिल लाया है, वह सही नहीं होगा।

बड़ी विनम्रता के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो उत्पादन के आधार पर, जिस क्षेत्र में जहां जिस रूप से उत्पादन होता है, आप जब तक उस उत्पादन के आधार पर वहां आईआईटी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लोहा कहीं होता है और कहीं और बगैर लोहा के आईआईटी वहां कर देंगे। इससे आपकी पूंजी भी ज्यादा लगेगी और बच्चों को नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। हमारे बिहार से 42 लाख मज़दूर हमेशा बाहर काम के लिए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कहीं किसी का सम्मान आईआईटी से ले कर किसी टैक्नोलॉजी में है, तो बिहार का है। आप याद कीजिए मैथ्स से ले कर, शून्य से ले कर, आर्यभट्ट से ले कर आज तक बिहार की जो स्थिति है, वह सबसे ऊपर है। लेकिन एक भी आईआईटी बिहार में नहीं है। हमारा जो कोसी का इलाका है, मिथिला, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, जो मिथिला इलाका है, वहां क्या क्वालिटी नहीं है। बांस की क्वालिटी है, मकान की है, माच की है, केला की है, लीची की है और हमारे यहां का मज़दूर पूरी दुनिया को बनाता है। अभी ये पंजाब-पंजाब कह रहे थे, पंजाब को बनाने में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। भारत बनाने में बिहार का योगदान है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि इसमें आप कोऑपरेटिव सिस्टम क्यों नहीं लाते हैं। आप पीपीपी सिस्टम तो ला रहे हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम को फर्टिलाइज़ क्यों नहीं करते हैं? अगर आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लाएंगे तो मिडिल क्लास और किसान वर्ग भी इसमें शामिल होगा तो निश्चित रूप से वह अपने बच्चों के लिए पेन लेगा। मेरा आग्रह है कि बिहार में कम से कम पांच आईआईटी की व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार देश का निर्माण करता है। विश्व में जाता है, सिलिकन वैली में जाता है, इसीलिए मैं आपसे सहरसा-मधेपुरा में और एक मध्य बिहार में राजगीर के इलाके में और तीसरा अन्य जगहों पर एक आईआईटी की मांग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें आप जमीन को कम कीजिए।

अंतिम बात मैं यह कह रहा हूँ कि जब तक बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो आपने दी नहीं हैं, नौकरी की स्थिति दो लाख से ऊपर नहीं हुई है, तो बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी। जब आप पूंजीपति को ला रहे हैं तो उसको कम्पलसरी कीजिए कि उसके स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे, उसको नौकरी की गारंटी होगी और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं, उनकी फीस कम कीजिए और 25 प्रतिशत गरीब के बच्चों को इसमें फ्री कीजिए। यह आपसे मेरा आग्रह है।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you, Hon'ble Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on an important bill.

Sir, I thank the Hon'ble Minister for piloting this bill in this august House. It will give a boost to higher education throughout India. As Shri Bhagwant Maan ji said during his speech, students who study in these institutes of higher learning in Punjab, often go abroad. It leads to brain-drain.

Sir, in Punjab, there is acute shortage of high quality information technology hubs. We need such hubs in Punjab. Also, Sir, there are certain shortcomings in the I.I.T. that is there in Punjab. These shortcomings must be removed by the Central Government.

Sir, as mentioned by me earlier, students who study in these institutes of higher learning, often join the jobs in foreign multi-national companies abroad. It leads to acute brain-drain. I urge upon the government to evolve such a system where it is made compulsory for students to work in one's own country and State for the first 5 to 10 years. The states and our country will gain out of it. On the other hand, there are students who fail to get a decent job despite studying in such institutes of higher learning. There is no evolved system in our country to deal with such kind of unemployment.

Sir, let me also point out that students belonging to the Scheduled Castes & Scheduled Tribes are generally not in a condition to shell out one to one and a half lakh rupees as fees. So, such students fail to avail the education provided by such institutes of higher learning. Scholarships and fee-exemptions should be granted to the SC&ST students too, so that they can study in I.I.Ts etc.

Hon'ble Deputy Speaker Sir, poor students from humble background are also very intelligent. The only thing they lack is sound finance to fund their educational needs. So, the government must bail out the students of these sections of society.

Sir, the scholarship system needs to be revamped in the Engineering Colleges. Scholarship system must be streamlined in all states, specially Punjab. Only then can the students reap the benefits offered by these Engineering Colleges.

Thank you.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I thank you for the opportunity.

Firstly, I would like to congratulate the Minister for bringing this Bill. I have been an IT professional. I was the Managing Director and CEO of several multi-national companies including Wipro and General Electric. I can feel the pressure from Shri Scindia and his anxiety for time. So, I will make it very short and I would like to limit myself to just a single point.

In the Statement of Objects and Reasons, one of the objectives was providing manpower of global standards. Yet, if you look at our IT professionals, while they are highly paid, still they are relatively less paid compared to their western counterparts. Moreover, if there is any stress in the industry resulting in layoffs, then the first victims are the Indian IT professionals. There is a reason for this. It is because mechanical engineers work in the field of mechanical engineering; electrical engineers work in the field of electrical engineering; civil engineers work in the field of construction; but IT engineers and IT professionals work in different fields. They work in the field of manufacturing, banking, movies, sports, hospitals, etc. Therefore, there is a need for not just exposure to programming, but a need for social science, liberal arts, performing arts, and all these other arts.

Many Members have said that we should introduce robotics, artificial intelligence and other new technologies, but more important than that is to introduce social sciences in the IIITs. So, my suggestion is that while we support, I would strongly suggest that the Minister adds this too. Thank you, Sir.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं सम्पूर्ण सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस चर्चा में 25 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन हर एक माननीय सदस्य ने इस बिल का सपोर्ट किया है। हमारे मित्र प्रेमचन्द्रन जी ने विरोध किया, वह भी उनका एक विÂषय सैद्धान्तिक मुद्दे पर था और जो पी.के.बिजू जी का कहना है, उस पर मैं कहूँगा। श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. कुलमणि सामल, श्री अरविंद सावंत, श्री बी.विनोद कुमार, श्री पी.के.बिजू, डॉ. रविन्द्र बाबू, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, श्रीमती वुला रेणुका, श्री सुरेश सी. अंगड़ी, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री धनंजय महाडीक, श्री दुÂष्यंत चौटाला, श्री शेर सिंह गुबाया, मालवीय जी, श्री राजेश रंजन, श्री भगवंत मान, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री प्रेम दास राई, श्री जोस के. मणि, शेखावत जी, श्री अधीर रंजन चौधरी आदि सभी ने इसका सपोर्ट किया है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे मूल यह होगा कि ट्रिपल आई.टी. एक अपनी अच्छी संस्थायें बन गयी हैं। पहले केवल चार ही ट्रिपल आई.टी. थीं, जो सरकार ने शुरू की थीं, जबलपुर, ग्वालियर, इलाहाबाद और कांचीपुरम और पाँचवीं अभी गवर्नमेंट फंडिड कुर्नूल में हो रही है, आध्र प्रदेश का विभाजन होने के कारण। ये पाँच ही हुई। अब विस्तार कब होगा, तो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का विचार विस्तार के लिए भी करना चाहिए। जो सबको आशंका है कि इसमें फीस बहुत बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिकरिंग खर्चे की ताकत केवल फीस से नहीं आती, वह रिसर्च ग्रांट से भी आती है, वह प्रोजेक्ट से भी आती है और जो वे खुद बाकी काम तैयार करते हैं और नया रिसर्च करते हैं,

उससे भी उनको पैसा मिलता है।

मैं मुख्य मुद्दों पर बात करूँगा। मैं याद कर रहा हूँ कि 1973 में मैं बैंक में नौकरी करता था, तब कंप्यूटर पहली बार आए। कंप्यूटर बैंक में आए तो पहले हम लेज़र पर काम करते थे। वह खत्म हुआ तो वहाँ यूनियन्स का आंदोलन हुआ कि एक कंप्यूटर 23 लोगों को बेरोज़गार करेगा। मैंने उस समय भी विरोध किया कि ऐसा नहीं होता। जो भी कंप्यूटर आता है, यह नई टैक्नोलॉजी है, इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए और जो कुछ लोगों ने श्रेय की बात की कि राजीव गांधी ने भी किया, इन्होंने भी किया। तो पहले प्रधान मंत्री हैं नरेन्द्र मोदी, जो हमेशा, हर बार, सदन में और बाहर भी कहते हैं कि इस देश में आज तक जो तरक्की हुई, उसमें सभी सरकारों और सभी प्रधान मंत्रियों का कंट्रीब्यूशन है। हमें इसको और आगे ले जाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, यह वृत्ति हम रखते हैं। सैम पित्रोदा ने टेलीकाम रेवाल्यूशन में एक भूमिका निभाई, यह सही है। अब नंदन नीलेकनी जी ने आधार का एक इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और शुरू किया। आपने आधार में हाथ छोड़ दिया। अभी हम आगे ले जा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं।

जब अटल जी प्रधान मंत्री थे, तो आईटी फॉर मासेज़ नाम का भारत सरकार का वर्किंग ग्रुप था, मैं उसका अध्यक्ष था। हमने ई-गवर्नेंस के बहुत से इनीशियेटिव्स बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गए, आज कहाँ तक पहुँच गए। We are a soft power. जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें इसका अभिमान है, लेकिन हमारी कमियाँ भी हैं। हमें समझना चाहिए। हम सॉफ्टवेयर में आगे आ गए, लेकिन हार्डवेयर में नहीं गए। हम सॉफ्टवेयर में एक ब्रांच में एक तरफ से अलग गए और बीपीओ का काम कर रहे हैं, लेकिन न हमने गूगल तैयार किया, न फेसबुक तैयार किया, न ट्विटर तैयार किया, न विंडोज़ तैयार किया। हमारी प्रतिभा विदेशों में यह सब उपकरण तैयार करने में लगी है। वह दूसरे लोग कर रहे हैं जिसमें हमारी टीम है। लेकिन वह हमारी मिल्कियत नहीं है। इसलिए we must attract back the best of the best talents. हमारा टेलेंट कितना है, इसके लिए बिल गेट्स ने भी कहा जब लोगों ने उनको पूछा कि आप इतने इंडियन इंजीनियर्स क्यों अपनी कंपनी में भर्ती कर रहे हो? Why are you recruiting so many Indian engineers in your company? He replied, "If I don't do that, they will create a parallel Microsoft in Bengaluru." यह उन्होंने कहा। इसलिए भारतीय प्रतिभा है, लेकिन मिल्कियत हमारे पास नहीं है, वह लानी है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो मेक इन इंडिया कह रहे हैं, वह मेक इन इंडिया इसीलिए है। What is Make in India? It is, come, invest, innovate, and Make in India, and sell with pride as Made in India. That is what the Make in India vision is. इसको लेकर हमें आगे जाना है। अब तो दुनिया इतनी ज़बर्दस्त गति से बदल रही है कि 1000 साल में जो नहीं हुआ, वह पिछली एक सदी में हुआ है। जो पिछली एक सदी में नहीं हुआ, वह आने वाले दस सालों में होने वाला है। दुनिया बहुत गति से बदल रही है। उसके लिए आधुनिक शिक्षा चाहिए, उसके नेशनल इंपेर्टिंस के संस्थान करने चाहिए, इसलिए यह बिल है। इसमें सबकी भागीदारी चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप का महत्व कम न करें। नैनो टैक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनैट ऑफ एथ्रीथिंग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस आ रहा है, थ्री डी प्रिंटिंग आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है। स्टूडेंट्स को यह सब सीखने का मौका होना चाहिए। मैं पिछले सप्ताह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज़ में गया था। वहाँ नैनो टैक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है, एक प्रयोगशाला में 250 करोड़ रुपये लगे हैं। और भी एक केन्द्र का निर्माण करना है जिसमें 3000 करोड़ रुपये लगेंगे, लेकिन इनवैस्टमैंट ऐसा करना चाहिए क्योंकि We have lost. इंडस्ट्रियल रिवाल्यूशन जब आया तब हम चूक गए क्योंकि तब हम स्वाधीन नहीं थे। जब हार्डवेयर रिवाल्यूशन आया तो वह भी हमसे चूक गया। अब एक भी आने वाली रिवाल्यूशन हमसे चूकनी नहीं चाहिए। अगर यह हमें करना है तो With that vision, we must work, and we must do justice to our students and talent. टेलेंट है जैसे पप्पू जी ने कहा कि सब वर्गों में टेलेंट है। टेलेंट किसी वर्ग की मिराजदारी नहीं है, किसी जाति या मज़हब की नहीं है। यह सब है, इसीलिए हमने इस बार प्रयोग किया। प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथान का आयोजन किया। 2000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों ने भाग लिया। Around 42,000 students participated in Hackathon and came out with solution. They worked hard on problems. We offered them 600 problems. About 42,000 students worked on it for three months. Ultimately, they came out with 200 solutions. That is a real study. यह सही शिक्षा है।

हुड्डा जी ने यू.एस. और ऑस्ट्रेलिया की आशंका उठाई, वह एक तरह से सही लगती है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी हो रही है। लेकिन, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। वे पीछे पड़े हैं कि आप यहां रहो। हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि वे यहां अच्छी सुविधाएं प्राप्त करें और यहां वापस आएं। लोग आ भी रहे हैं और यहां अच्छा भी होगा।

एक टिप्पणी हुई कि आई.टी. क्षेत्र में बेरोज़गारी बढ़ रही है। यह सच नहीं है। टी.सी.एस. के मुखिया चन्द्रशेखर जी और नैस्कॉम, दोनों ने अंदाज़ लगाया है कि आने वाले पांच सालों में 70 लाख नए रोज़गार केवल आई.टी. क्षेत्र में सृजन होंगे। यह होने वाला है। भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।

प्राइवेट एजुकेशन है, इंवेस्टमेंट है। इसलिए इसके विस्तार में इनकी जरूरत है। यही तो अलाइनमेंट-विद-स्टडी है। Unless we ensure industry-academia interaction, we would not reach the destination where we want to reach.

दो-तीन जो आशंकाएं आई हैं, उसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आई.आई.आई.टी., अमेठी के बारे में आपत्ति जताई गयी। ऐसा है कि यह आपत्ति न उठाते तो अच्छा होता, क्योंकि यह छिपी रहती। लेकिन, अब आपत्ति उठायी गयी है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। वर्ष 2005 में आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद का ऑफ कैम्पस आई.आई.आई.टी., अमेठी में बनाया गया था। लेकिन, वर्ष 2014 तक, नौ सालों तक वहां फैकल्टी नियुक्त ही नहीं की गयी थी, केवल एक फैकल्टी को नियुक्त किया गया था। रोज़ इलाहाबाद से वह फैकल्टी अमेठी जाकर रोज़ चार लेक्चर देकर अपना विषय पूरा करता था। फिर दूसरे दिन दूसरा फैकल्टी जाता था। यह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है। इसलिए पूरे देश भर से छात्र आए। उनका पहला प्रेफेरेंस इलाहाबाद था। उन्हें इलाहाबाद में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए उन्हें लगा कि अमेठी तो बहुत ही शानदार होगा, सबसे ज्यादा सुविधाएं होंगी। छात्रों का ऐसा सोचना सही था, लेकिन वहां ऐसी सुविधा नहीं थी। वहां सब-स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलने लगा। तब जाकर सभी छात्रों ने आंदोलन किया कि हमें यहां से बदलो, हमारी मुख्य संस्था इलाहाबाद है, हमें वहां ले जाओ। हमने कोई प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया। छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए उन्हें केवल वहां दे दिया। उसमें दस सालों में अमेठी जिले का केवल एक छात्र आया, क्योंकि इसमें छात्र ऑल इंडिया कम्पीटीशन से आते हैं। सुलतानपुर के केवल तीन छात्र आए। फिर हमने क्या किया, वहां उसी केन्द्र में अम्बेडकर विश्वविद्यालय का केन्द्र निकाला और वह कॉलेज अब अच्छा चलने लगा है और अमेठी और सुलतानपुर जिले के हजारों छात्रों को फायदा हो रहा है। यह हमारी टÂिष्ट है। आपने नहीं किया तो हम रुके नहीं। हमने उसे बंद नहीं किया, बल्कि वहां कॉलेज शुरू किया, जो वहां के लोगों की जरूरत थी।

एक विÂषय स्टेट शेयर का आया। अब स्टेट्स को भी बहुत पैसे मिले हैं। कितना मिला है, यह वित्त मंत्री बताएंगे। लेकिन, एक ही बार में उनका हिस्सा 32औ से बढ़कर 42औ हो गया। हर बार वित्त आयोग केवल दो प्रतिशत बढ़ाता था। अब 32औ से बढ़कर 42औ हो गया और 7.5औ सिक्कि बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, नगर परिÂषद, नगर पंचायत, उनके लिए भी पैसे मिले। केन्द्रीय योजनाओं का भी पैसा मिल रहा है। सबको जोड़ेंगे तो करीब 75औ पैसा राज्यों को जाता है। यह सही है। इसे मैं कोई बुराई नहीं मानता हूं, यह अच्छी चीज़ है। राज्यों को फिर एजुकेशन को पैसे भी देना चाहिए। राज्यों के बजट में एजुकेशन के लिए पैसे कम नहीं होने चाहिए।

हमारे पोखरियाल जी ने कहा कि हिमालय का इतना अच्छा परिसर है, तो काशीपुर में आई.आई.एम. है, मंडी में आई.आई.टी. है। इसका और विस्तार होता रहेगा और यह सब जगह होगा।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी ने पूछा है कि क्या वहां पर परमानेंट बिल्डिंग होगी? मैं कहना चाहता हूं कि उसकी कंपाउंड वॉल का काम पूरा हो रहा है और बाकी बिल्डिंग भी जल्द पूरी होगी। अगर पी.पी.पी. इंटर्नल रिसोर्सेज़ से बढ़ेगी, तो क्या फीस बढ़ेगी? देखिए फीस पे करने वालों की बढ़ेगी यानी जो पेइंग कैपेसिटी है, उसके लिए थोड़े ही बढ़ती है। गरीब विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप योजना है। All these IIITs are already on the scholarship portal of the Ministry of IT. मिनिस्ट्री ऑफ आई.टी. का स्कॉलरशिप का एक पोर्टल है, उस पर सभी चीजें हैं। गरीब विद्यार्थी तथा अच्छे छात्रों को वहां पर सुविधा मिलती है। एक इम्प्लॉएब्लिटी का विषय निकला है। मैं कहना चाहता हूं कि इम्प्लॉएब्लिटी 25 पर्सेंट है, इसलिए हम उसका वैल्यू एडिशन कर रहे है जिससे कि छात्रों को सही शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे आगे बढ़े। इम्प्लॉएब्लिटी तभी बढ़ती है, जब सार्थक शिक्षा का प्रचार होता है, प्रसार होता है और अच्छी संस्थाएं बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे–ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज निकले, आपके समय या किसी दूसरे के समय, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन सच्चाई है कि ए.आई.सी.टी.ई. ने उस समय ऐसे–ऐसे परमिशन दे दिया कि जो रद्दी कॉलेजेज़ थे, जिसे स्टूडेंट्स ने ही रिजेक्ट किए थे। अब प्रत्येक साल डेढ़ सौ कॉलेज स्टूडेंट्स बंद कर रहे हैं, सरकार नहीं बंद कर रही है। हम तो केवल क्लोजर की अनुमति दे रहे हैं। स्टूडेंट्स वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर प्लेसमेंट कितना है और पिअर–रिव्यू लेते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। छात्रों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए ट्रिपल आई.टी. एक अच्छी व्यवस्था है। अब इसका विस्तार होगा।

जहां तक वैकेंसी की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि वैकेंसी सभी इंस्टीट्यूट्स में जल्दी से भरें, इसका हम बहुत ही जोर से प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिल रही है।

एक दूसरी चीज है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। हमारे श्री पी.के. बिजू जी ने कहा कि शिडयूल्ड कास्ट तथा शिडयूल्ड ट्राइब्स के फैकल्टी की वैकेंसी नहीं भरी गई है। आपका ऐसा कहना बहुत मात्रा में सही है। अब जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी की स्थिति को देखें, तो वहां दस साल से शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्स और दिव्यांग लोगों की भर्ती

नहीं हुई है। अब हम तीन सौ प्राध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं और यह काम दिसम्बर महीने तक पूरी होगी। हम लोग इस काम को सभी संस्थानों में करेंगे।

जैसा श्री पी.डी. राई जी ने कहा कि नॉर्थ–ईस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मणिपुर में ट्रिपल आई.टी. फंक्शनल है और गुवहाटी में भी फंक्शनल है। आपने कहा कि इसे सिक्किम में भी किया जाए; "दिल मांगे मोर' यह ठीक है और आपकी कल्पना अच्छी है। रिजर्वेशन के सारे नियम लागू होते हैं। इंडियन लॉ सभी जगह लगता है। बहुत सारे मुद्दे थे, सबका उत्तर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अच्छे मुद्दे थे। मैं सभी लोगों के सुझावों का स्वागत है। मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा पार्टीगत या दलगत राजनीति का विÂषय नहीं है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यह राष्ट्र नीति का विÂषय है, देश बनाने का विÂषय है। इसमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इसको सभी लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to declare certain Indian Institutes of Information Technology established under public-private partnership as institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 48 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 48 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.